राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्यय सत्र की कार्यवाही

अष्टम बैठक बृहस्पतिवार, दिनांक १० अप्रेल, १९५२ ई०

सभा की बैठक आज तारीख १० अप्रल, सन् १९५२ ई०, को सवाई मानसिंह टाउनहॉल, जयपुर, में ८ बजकर ३० मिनट पर प्रारम्भ हुई। माननीय अध्यक्ष श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पद पर आसीन।

लेखा-समिति के सदस्यों की नामजदगी।

माननीय अध्यक्ष-उपनियमों की धारा १४० के अन्तर्गत एकाउन्टस कमेटी की नामजदगी के लिए जिसकी कि कल घोषणा की गई थी ५ सदस्यों का चुनाव होने को था, और मेरे पास ५ सदस्यों की नामजदगी के फार्म आये हैं, जिनका मैं चुना जाना घोषित करता हूं। वे ये हैं:—

१. श्री हरिदत्त,
२. श्री कानसिंह
३. श्री वेदपाल त्यागी
४. श्री मथुरादास माथुर
५. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल

(हियर—हियर)

यह धारा १४० (४) के अन्तर्गत अपना सभापति स्वयं निर्वाचित करेंगे।

आय-व्यय पर सामान्य वादविवाद।

माननीय अध्यक्ष:—अब बजट के ऊपर साधारण वादविवाद प्रारम्भ किया जाता है।

श्री माधोप्रसाद:—स्पीकर महोदय, मैं बजट के विषय पर कल एक दूसरी चीज निवेदन करना चाहता था, किन्तु मेरे दल के नेता और उपनेता के भाषण होने पर मैंने विचार किया कि हमारी बहुत सी बातें विरोधी हैं: तो पहले विचार करके देख लेना चाहिए। मैं दो एक बातों का विरोध करना चाहता हूं। हमारे दल के नेता (श्री जसवन्तसिंह) ने कहा कि शराब पर कर नहीं लगाना चाहिये।

मैं कहता हूं कि उस पर अधिक से अधिक कर लगाना चाहिए। आठ आना हो तो १ रु० लगाना चाहिए। ऐसे और भी कई विषय हैं जिनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दूसरे पक्ष की होते हुए भी उत्तम हैं और उसमें कहीं कोई एकाध कमी होगई हो तो उससे कोई सारा बजट खराब नहीं हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, जो बातें हमारे नेता ने कहीं हैं जैसा कि १७ करोड़ रुपये की बात-वह हमारे पास थे सो कहां गये तथा जो मंत्रियों को वेतन मिलता है वह बहुत अधिक दिया गया ह। इत्यादि।

बजट का काम सरकार का है। जो कमी उचित नहीं है उस पर हमें निवेदन करना चाहिए। इस विषय पर मेरा विचार दिल में होते हुए भी कि मैं बोल सकता हूं या नहीं; मैंने सोचा कि इस पर विचार करूं। इस पर मैंने विचार किया तो यह विचार आया कि जैसा हो बोलना चाहिए। सर्वमान्य पं० मदन मोहनजी मालवीय कहा करते थे कि "यद्यपि शुद्धम् लोक विरुद्धम् नाकरणीयम् ना चरणीयम्" इसका मतलब यह है कि अपने पक्ष के विरोध की बात पहले नहीं करना चाहिए। मैंने विचार किया और फिर भी विचार करके देखा तो दिल में यह भावना दृढ़ हुई कि जो कुछ बात सच्ची है वह अवश्य कहनी चाहिए। उसमें कुछ भी हो, चाहे वह विपरीत हो या पक्ष में, म सच बात कहना चाहता हूं; इस संबंध में मेरा विचार है कि जो बजट पेश किया गया है बहुत अच्छा है।

केवल एक करोड़ का घाटा लगने से वह बुरा नहीं कहा जा सकता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि एक करोड़ तो क्या दो करोड़ का भी घाटा हो तो; उसे हम पूरा कर सकते हैं। संसार में दो ही तरीके हैं। घाटा पूरा करने के लिए, एक तो कर के द्वारा और दूसरा ऋण से। ऋण से घाटा पूरा करने से नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ होता है। यह बात आज की नहीं हजारों, लाखों वर्षों से चली आ रही ह। हमारे यहां चार्वाक जो सच्चा अर्थशास्त्री था उसन भी कहा है कि "यवज्जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम् पीवेत्" अर्थात्, खावो पीओ, मौज करो' जीवन का अन्त जो है वह मौज करना है। (हियर, हियर) Eat drink and be merry का यह सिद्धान्त जो है वह उत्तम सिद्धान्त है। यह अर्थशास्त्रियों के विचार है। यह भी कोई अर्थशास्त्री कहता ह वह बुरी बात नहीं है। अर्थशास्त्री इस संसार की बातों पर विचार करता है, परलोक का विचार नहीं करता है। उसका काम है यह देखना कि हमारा देश सुखी व समृद्ध हो, वही काम हमें करना चाहिए। ऋण लेकर भी आप काम करें। मैंने अपने जीवन में देखा है कि हजारों, नहीं लाखों आदमियों को कि जो २००), ५००) रू० लेकर बाहर गये और व्यापार किया। वे आज करोड़पति हो गये हैं। ऐसे एक नहीं करोड़ों आदमी हैं। इसी तरह एक राष्ट्र भी ऋण ले सकता है। राष्ट्र को ऋण लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए और खूब खर्च करना चाहिए, किन्तु अपव्यय को रोकना चाहिए।

कल जो यह कहा गया कि १७ करोड़ जो राज्यों से मिले थे वह कहां गये। उसका हिसाब बनाना सरकार का काम है। मंत्रियों के संबन्ध में यह आक्षेप किया गया है कि उन्हें जो वेतन दिया गया है वह बहुत सी जगहों से

ज्यादा है । उसका उत्तर वे देंगे । मैं तो आपको बताऊंगा कि कर लगना उचित है या या ऋण लेना । मेरी राय में ऋण लेना कर लगाने के बजाय उचित है । जो विलायत है वहां भी नेशनल डेट (राष्ट्रीय ऋण) होता है उनके मुकाबले में नेशनल डेट अन्यत्र कहीं भी नहीं है । उसके बारे में उनको चिन्ता नहीं है कि वह कितना हैं । यह तो एक क्रेडिट है । जितना अधिक ऋण लेकर आप काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ऋण मिलता हो, तो आप चाहे जो खच कर सकते हैं, और उतना ही आपका अधिक श्रेय है, प्रतिष्ठा ह ।

अध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय एक और आपत्तिजनक जनक बात जो है वह यह कि शराब पर टैक्स यदि लगता है तो शराब पर ८ आने के बजाय १) रु० लगाना चाहिए । शराब को बन्द करना चाहिए । इसी तरह आमोद प्रमोद के जो साधन हैं, जैसे सिनेमा हैं, नाटक हैं तथा दूसरे लग्ज़रीज़ (Luxuries) के जो साधन ह, जैसे, तेल, इत्र हैं और बहुतसी चीजें हैं, उन सब पर टैक्स लगना चाहिए । खेती पर टैक्स नहीं लगना चाहिए । यह किसान लोगों क लिए बहुत बड़ी आपत्ति की बात हैं । नमक और खेती पर टक्स लगाने के लिए तो अर्थशास्त्र भी विरुद्ध ह ।

सबसे पहले तो यह सवाल था कि दल में रहते हुए कोई बात दल के नेता के विरुद्ध कही जा सकती है या नहीं । इस विषय में मेरा कहना है कि अन्तर्आत्मा दल से ऊपर है (हियर, हियर) । जो खरी बात है वह कहनी चाहिए । आपने देखा होगा कि हमारे यहां ऐसे बड़े २ नेता हो गये जिन्होंने बलिदान होने पर भी सच्ची बात कही । महात्माजी ने सत्य के लिए बलिदान दिया अपना शरीर भी दे दिया था, किन्तु सत्य का पक्ष नहीं छोड़ा । एक आदमी होकर सत्य कहे और सत्य कहना चाहिए । सत्य कहना कोई बुराई नहीं है । मेरा यह निवेदन ह कि बजट उत्तम से उत्तम है । जो बुराइयां है वह निकाल देना चाहिए । उसमें एक बात और ऐसी है बजट के संबन्ध में कि वित्तमंत्री जी डर गये ओर यह घबराकर कहने लगे कि आप इसको पसन्द करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि बजट तो नीरस होता है; बजट में नीरसता भरी हुई होती है, लोग सो जाते है । इसका मतलब यह नहीं कि वह बजट खराब है । मेरे भी पार्लियामेंट में एक मित्र साथी हैं; वह कहते है; कि बजट म सब जगह लोग सोते है, इंगलेंड में भी हाउस आफ कॉमन्स में जब बजट खुलने का होता है तो बजट को लोग डिनर बेल समझते हैं; किन्तु इससे ही तो कोइ बजट खराब नहीं हो जाता है ।

बजट में आपने बहुत सा इन्तजाम किया है, शिक्षा का, सिंचाई का और बहुत से रास्तों का (कम्युनिकेशन्स) जो कि बहुत आवश्यक है, यह सब मैंने देखा है कि उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर सब जगह की बातें लेकर बजट बनाया गया है । एक साथ में सब जगह नहीं कर सकते हैं । धीरे धीरे लेकर पूरा कर सकते हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि बजट खराब है ।

बजट के संबन्ध में एक बात जो कही गई है वह सलाहकारों के संबन्ध में है । यदि वास्तव में सलाहकारों की जरूरत नहीं है तो यह खर्चा कम किया जा सकता है । इसके लिए सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता ।

सरकार का करोड़ों रुपया कई व्यवसायों में कई कम्पनियों में लगाया हुआ है । इसका निर्णय सरकार कर सकती है कि वह रुपया ठीक तरह से लगा हुआ है या नहीं । अकाउन्ट कमेटी बनाकर यह जांच करे कि वह रुपया अनुचित तो नहीं लगाया गया है । यदि अनुचित लगाया गया है तो उसे वापिस ले लेना चाहिये । एक बात यह है कि किसानों पर जो कर लगाया जा रहा है वह किसी भी हालत में नहीं लगाया जाना चाहिये । हरेक सरकार दो तरह से अपना घाटा पूरा कर सकती है एक तो कर लगाकर दूसरा ऋण लेकर । अंग्रेजों का इतिहास आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि चार्लस फर्स्ट ने कर लगाया तो उसे अन्त में उसके लिए सिर देना पड़ा । उसके बाद जब वे ऋण लेने लगे तो वहां की स्थिति सुधर गई । इससे आज उनके ऊपर इतने करोड़ रुपयें का ऋण है और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है । ऐसी प्रतिष्ठा भी हमारी होनी चाहिये; ताकि हमें कोई ऋण दे सके ।

आमोद प्रमोद के साधनों पर लग्जरीज (Luxuries) तेल इत्र आदि पर जितना कर लगाया जाय लगाना चाहिये । लोग कहते हैं कि चार्वाक अनाचारी था । मैं कहता हूं कि वह एक बहुत बड़ा अर्थ-शास्त्री था । उसका कहना था संसार में जीओ, खूब मौज से जीओ ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—माननीय सदस्य के विचार बहुत सुन्दर हैं लेकिन वे अपने विषय से विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री माधवप्रसाद:—मैं बजट के विषय में ही कह रहा हूं । मेरी मान्यता है कि चार्वाक अनाचारी नहीं था वह बहुत बड़ा अर्थ-शास्त्री था । वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह उत्तम से उत्तम बजट है । इसमें कई दोष हो सकते हैं लेकिन जो यथार्थ में बात हो वही कहनी चाहिये; संकोच नहीं करना चाहिये ।

श्री मदन मोहन:—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से दो रोज पूर्व हमारी नव-निर्मित सरकार के वित्त मंत्री ने अपना वार्षिक बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया था; जिसमें सरकार के आय व्यय का ब्योरा दिया गया था । संसार के सभी जनतंत्री राज्यों में इस प्रकार के बजट पेश किये जाते ह और जो सिद्धान्त ऐसे बजट पेश करने में निहित हैं वह यह है कि देश में कोई नया कर प्रजा के नुमायन्दों की सम्मति के बिना न लगाया जाय और इस प्रकार कोई नया व्यय बिना जनता के नुमायंदों की सम्मति के स्वीकृत न किया जाय । इस प्रकार हमारे देश में भी यह पहला बजट इस सदन के सामने पेश किया गया ह जिस पर साधारण वाद विवाद होने को है । इसमें जहां तक इस सदन के सदस्यों का हाथ हो सकता है । मेरा ख्याल है कि हम सरकार की जो पोलिसी आज तक रही है इसका रिव्यू, (सिंहावलोकन)करते हुए उस पर प्रकाश डालेंगे व इसके साथ ही जो तकलीफात के उजरात (Grievances) जनता को रहे हैं उनको सदन के सामने रखने का प्रयत्न करेंगे । हम जानते हैं कि जनतंत्र राज्यों में जिस प्रकार कि इंगिलस्तान के हाउस आफ कॉमन्स में जहां की प्रणाली की नकल हम इस सदन में कर रहे हैं, इन दो बातों के सिवाय सदन के सदस्य कोई विशेष काट छांट इस बजट में नहीं कर सकते । ऐसी परम्परा ह । जिस वक्त इस

सदन के मेम्बर सप्लाई कमेटी और वेज़ एण्ड मीन्स की कमेटी के तौर पर बैठेगें और बजट के अन्दर निर्धारित अलग अलग आंकड़ों पर उन्हें मन्जूर करना या उन्हें अस्वीकृत करने के लिए विचार करेगें उस वक्त देखा जायगा कि कौनसे नये कर लगाने की सम्मति यह सदन देता है और किस नये व्यय की स्वीकृती यह सदन देता है । मगर आज इस सदन में वाद-विवाद चल रहा है उसमें हमें उन आंकड़ों की तरफ नहीं जाना है । इसलिये मैं सदन के सदस्यों का अमूल्य समय इनकी चर्चा कर नहीं लूंगा ।

कल से जो वाद-विवाद इस सदन में बजट पर चल रहा है उससे एक बात समझ में अवश्य आती है कि इस सदन की दोनों पार्टियां इस बजट से सन्तुष्ट नहीं हैं । सदन के कोने कोने से यह आवाज बुलन्द होती सी नजर आती है और सुनाई देती है कि हमारे मुल्क की, हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति संभाले रखने में अब तक की सरकार कामयाब नहीं रही । जो कुछ नीति अब तक अपनाई गई है उससे जितना लाभ होना चाहिये था उतना नहीं हो सका है ।

बजट के अपने वाद-विवाद को मैं इस सदन के सामने चार हिस्सों में प्रस्तुत करूंगा । वे चार हिस्से प्रश्नों के रूप में ये हैं । बजट में घाटा क्यों है और उसके लिए दोषी कौन है ?. दूसरा प्रश्न है घाटा उठा कर भी हम कोई जनहितकारी काम करने में सफल हुए हैं या नहीं ? और हमारे प्रान्त की क्या स्थिति है ? तीसरी चीज उसकी पूर्ति के क्या साधन हो सकते हैं ? यह पूर्ति न होने की सूरत में जनसाधारण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? चौथा प्रश्न जो मैं अपने वाद-विवाद में प्रस्तुत करूंगा वो यह है कि हम सब लोगों का ऐसी हालत में क्या कर्तव्य है ।

जहां तक पहले सवाल का सम्बन्ध है मैं यह बात निशंकोच कहने के लिए तैयार हूं कि जो स्थिति घाटे की बजट में रही है उसकी जिम्मेवारी अब तः की जो सरकार कांग्रेसी मित्रों की रही है उसी पर रही है । ३ वर्ष से हकमत की बागडोर जिन मित्रों के हाथ में थी उन्होंने ऐसी स्थिति बनादी जिसे देखकर हमें सिवाय आश्चर्य के और कुछ नहीं हो सकता । कल के वाद-विवाद में मेरे कई मित्रों ने इस बात पर प्रकाश डाला था जिस वक्त कांग्रेसी सरकार ने हमारे मुल्क की बागडोर अपने हाथ में ली उस वक्त हमारे पास स्थायी कोष में १७ करोड़ रुपये थे । दुःख तो हमें इस बात का है कि एक बनी हुई बात को हम नहीं बना सके तो एक बिगड़ी हुई बात तो हमारे लिये बनाना बहुत ही मुश्किल है। कम से कम जितनी रियासतों का इन्टीग्रेशन हुआ और जितनी रियासतें राजस्थान में मिलीं उस वक्त कुछ न कुछ पैसा रियासतों ने राजस्थान सरकार को अवश्य दिया था क्योंकि उन तमाम रियासतों का बजट उस वक्त घाटे में नहीं चल रहा था । कुछ छोटी मोटी रियासतें ऐसी थीं जिनके पास पैसा नहीं

था। मगर फिर भी जितनी भी बड़ी रियासतें थी उनके बजट घाटे में नहीं थे। परन्तु यह अफसोस का विषय है कि हमारी स्थिति अच्छी होते हुए भी हमारा पहला बजट घाटे का बजट है।

दूसरी चीज जिसकी तरफ मुझे आपके मारफत सदन का ध्यान आकर्षित करना है वह यह है कि घाटा करके भी यदि हम कोई जनहित कार्य करने में सफल हुए हैं या नहीं ? और इस संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि एक दलील के तौर पर यह बात कही जा सकती है कि हमारे मुल्क की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी; हम बहुत पिछड़े हुए थे; हमें काफी जनहित के कामों पर पैसा लगाना पडा। मगर मैं यह कहूंगा कि जहां तक यह दलील है, दलील ही रह जाती है। यदि घाटा करके भी कोई ठोस कदम जनहितकारी कार्यों की तरफ बढा सके होते तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि घाटा वाकई ठीक है और जो काम हमने किये हैं वाकई जनहित के काम हैं और उनके करने में घाटा हुआ। मगर मुल्क की जैसी भी हालत है उसके संबन्ध में मैं थोड़े से शब्द आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं, जिस मसले पर सदन के काफी लोगों ने पूरे तौर से रोशनी डाली है।

हमारा मुल्क एक कृषि-प्रधान देश है और ज्यादा लोग गांवों में ही रहते हैं। क्या में सरकार से इस सदन के तुच्छ सेवक के नाते दरियाफ्त कर सकता हूं कि जो कुछ खर्चा लगाया गया है उससे क्या उन लोगों को कोई फायदा हुआ ? गांवों की जैसी स्थिति है वह आप सदन के किसी सदस्यों से छुपी नहीं है। आप किसी गांव में चले जावें। वहां पर आप गंदगी का ढेर, नंगे-पतले-भूखे प्राणियों के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आवेगा; जो छोटे-मोटे मकानों में दुःख से अपना जीवन बिता रहे है। मेरे खयाल से इस ग्रामीण जनता के लिये जो कुछ खर्च किया गया बताया जाता है उसका लाभ उन्हें नहीं पहुंचा। दूसरी चीज शिक्षा के सम्बन्ध में अर्ज करता हूं। अभी मेरे एक साथी ने बजट की सराहना करते हुए यह बतलाया था कि बजट सर्वांगपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि के लिये कई अच्छी बातें रखी गई है और सरकार की ओर से खर्च करने की बातें कही है, लेकिन इस संबंध में म यह अर्ज करूंगा कि शिक्षा की जो हालत है वह सदन के सदस्यों से छुपी नहीं है। हमारी सरकार ने आज तक जो कुछ शिक्षा के लिए खर्च किया है वह सिर्फ एक प्रोपेगेन्डा के रूप में खर्च किया (हिअर हिअर) बहुत ज्यादा रकम एडल्ट शिक्षा ` सम्बन्ध में खर्च की गई। इसके लिये जगह-जगह सभाएं हुई, जलसे बुलाये गये, मगर मैं यह दर्यापत करूंगा कि वास्तव में कितना काम हुआ ? मुझे विश्वास है कि जहां से मैं आ रहा हूं उस स्थान पर सात रोज तक बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई और उनको ग्राम ग्राम में घुमाया गया, पैसे इकट्ठे किये गये; मगर उसका कोई नतीजा नहीं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के स्वतन्त्र होने के बावजूद भी हमारी शिक्षा की वही हालत है जो स्वतंत्र होने के पहले थी। इसको सुधारने के लिये सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। जो तालीम पहले दी जाती थी वही तालीम आज भी दी जाती है। जो कुछ खर्च लगाया जाना बताया जाता है

वह चन्द स्कूलें इधर उधर खोली जाने में, जिनको हम स्कूलें समझ नहीं सकते हैं नाम मात्र की स्कूलें कह सकते हैं, जहां मास्टर हैं तो लड़के नहीं; कहीं मास्टरों को तनख्वाहें नहीं मिलती और उसके फलस्वरूप वो नौकरी छोड़ कर चले जाते हैं या यों कहिये की फजूल तनख्वाह लेते हैं, में लगाया गया (चीअर्स) इसके सिवाय कोई खास फायदा नहीं हुआ ।

चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि चिकित्सा का काम करने वाले डाक्टर और नर्सेज से जो जो वायदे तनख्वाह बढ़ाने के लिये किये गये वे अभी तक पूरे नहीं किये गये । अगर आप एफिशिएन्ट (Efficient) कार्य करना चाहते हैं तो जो कुछ हमारे राजस्थान में थोड़े से सफाखाने हैं उनमें भी काम ठीक तरह से हो सकता है । मेरा खयाल है कि डाक्टर और नर्सों की तनख्वाह को ठीक करने के वायदे जो पूरे नहीं किये गये हैं उन्हें सरकार को शीघ्र पूरा करना चाहिये । आज शफाखानों में दवाइयें नहीं मिलती है । मैं जिस जगह से आ रहा हूं वहां की हालत आपसे अर्ज करूं तो आपको आश्चर्य होगा कि घावों पर बांधने के लिए पट्टियें तक हमको अपने घर से ले जानी पड़ती है । सर्विसेज पर काफी प्रकाश कल के वाद-विवाद में मेरे मित्र डाल चुके हैं मगर एक बात की ओर मैं इस सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि आजकल नौकरी करने वाले लोग कुछ हतोत्साह से हो रहे हैं और क्यों न हों; जिस तरह का सरकारी सिलसिला चल रहा ह जैसा कि हमारे पक्ष के नेता श्री जसवन्तसिंहजी ने कल अपने भाषण में सदन के सामने यह बात पेश की थी कि लोगों को वेतन समय पर नहीं मिलता । ओडिट वालों ने कुछ इस तरह के तरीके बना रक्खे हैं कि जो बिल बनाये जाते हैं उनका ठीक स्थान पर समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जिन कर्मचारियों को तीन–चार महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती ऐसी हालत में मामूली आदमी किस तरह अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं । मुझे अपने गांव के पास रहने वाले एक ऐसे शख्स का ख्याल है जिसने प्रोक्योरमेन्ट में चार महिनों तक नौकरी की, लेकिन उसको उसकी तनख्वाह नहीं मिल सकी । हमने तहसीलदारजी को इसके बारे में कहा, सप्लाई विभाग में बार बार अर्जियां भेजी कि इस शख्स ने चार महिने तक नौकरी की है आखिर किस बुनियाद पर इसकी तनख्वाह आपने रोक रखी है ? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला । इस तरह के इन्तजाम पर हमारी गवर्नमेन्ट को नाज होता है तो दूसरी बात है; वरना कोई समझदार आदमी इसे अच्छा नहीं बतायेगा । न्याय संबंधी बातों का एक वकील होने के नाते मुझे काफी जानकारी है और सदन के सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज कल जैसा न्याय हमारे न्यायालयों में उपलब्ध होता है वह जनता के काम का नहीं है, मुकद्दमे लम्बे होते जाते हैं । एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रान्सफर किये जाते हैं और अफसरों की भी बदलियें होती रहती हैं और इसके साथ ही मुकद्दमे नये सिरे से प्रारम्भ होते हैं । दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम जिन अदालतों का था उनका आज यह हाल है कि जीतने वाला हार समझता है व हारने वाला मौत समझता है।

जहां तक काश्त का सवाल है मैं पहले गांवों का जिक्र करते हुए अर्ज कर चुका हूं

कि हमारी ग्रामीण जनता को कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। काश्तकारों की वही हालत आज भी है जो २० वर्षों पहले थी। वही बेढंगी रफ्तार अब भी है; कोई नये किस्म के साधन उनके पास नहीं हैं। कोई नये इम्पलीमेन्ट्स उनके पास नहीं है। न नये किस्म की खेती है और न नये बीज ही उनके पास हैं। भगवान की कृपा से बारिश होने पर खेत में जाकर बीज डाल देते हैं। पैदावार अच्छी हुई तो भाग्य के भरोसे और न हुई तो भाग्य के भरोसे। न होने पर भाग्य को कोस कर रह जाते हैं। इन तमाम चीजों का बयान आपके सामने करने से मेरा मतलब यह है कि जो कुछ घाटा बजट में है वह यदि जनहितकारी काम करने के कारण हुआ होता और जैसी ही हालत इस मुल्क की है उसमें कुछ सुधार हुआ होता जैसा कि स्वराज्य बनते समय कल्पना की थी तो हम इस घाटे का ख्याल भी न करते लेकिन पहले से भी बदतर हालत देखकर कोई भी विचारशील आदमी सुख की नींद और सुख की सांस नहीं ले सकता।

टेक्सेशन का जिक्र करता हुआ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे बजट में दो तीन किस्म के नये कर लगाने का जिक्र किया गया है। एग्रिकल्चरल टेक्स का विरोध करता हुआ मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां के काश्तकारों की हालत नाजुक है और इसके लगाने से उनकी हालत और भी खराब हो जायगी। दूसरा टैक्स शराब पर लगने वाला है। मैं उसके बारे में कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। इस सम्बन्ध में एक बात यह है कि जिन जिन चीजों पर टैक्स लगाये जावें उनके बारे में इस बात का ध्यान रखा जाय कि इन टैक्सों से भ्रष्टाचार तो अधिक न बढ़ जायगा जैसा कि हमारे नेता ने कहा था कि शराब पर कर लगाने से कलाल लोग बेईमानी का काम करने लगेंगे; इसलिये इस तरफ कदम सोच समझ कर बढ़ाना चाहिये। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि टेक्सेशन ऐसी चीजों पर लगना चाहिये जो लग्जरीज कहलाती हैं। मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि "ऋणं कृत्वा घृतम् पीवेत्" वाली उनकी कहावत; यदि लग्जरीज पर टैक्स लगा दिये तो सच्ची न रहेगी क्योंकि इससे न तो घी मिलेगा पीने को और न दूसरी बातें रहेंगी। टेक्सेशन लगाये जायं और लोगों का यह फर्ज है कि अपने मुल्क की खुशहाली के लिये अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार के सामने रखें और इस तरह अपने मुल्क को कामयाब बनाने की कोशिश करें। लेकिन जसी भी मुल्क की हालत है उसे देखते हुए मैं अर्ज करूंगा कि कम से कम टैक्स लगाये जावें और जनता की हालत और ज्यादा नाजुक न बनाई जाय।

तीसरी चीज जिसका मुझे आपके सामने जिक्र करना है वह यह है कि यदि यही स्थिति रही तो उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस समय मुल्क की यह हालत जनता देखेगी तो उसका विश्वास दिन दिन सरकार पर से उठ जायगा। बजट में घाटा है और जब लोगों को विश्वास होगा कि जनहितकारी कोई काम नहीं हो रहा है और फिर भी घाटा है तो आप ख्याल फरमा सकते हैं कि उससे जनता को अविश्वास के सिवाय और कोई बात नहीं होगी। अब मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय सदन के सदस्यों का क्या कर्तव्य है? मुल्क के लोगों की नजरें

आपकी ओर लगी है। वे देखना चाहते हैं कि आप, १६० आदमी, एक साथ बैठ कर मुल्क के फायदे की क्या तजबीज सोचते हैं। ऐसी हालत में हमारा यह फर्ज है कि आपस के मतभेदों को मिटा कर एक दूसरे का सहयोग और सहायता लेकर एक दूसरे का विरोध न करके जनहित के काम करें और आपके मुल्क में जो अच्छे अच्छे आदमी हैं, जो किसी कारण से यहां नहीं आये हैं, उनकी भी सहायता लेने मे हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये। मुझे इसके साथ ही यह अर्ज करना है कि कल के वाद विवाद में कांग्रेसी दल की तरफ से यह कहा गया था कि बजट का विरोध हमारे विरोधी केवल विरोधी होने के कारण से कर रहे हैं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि उनकी यह धारणा भ्रम पूर्ण है। आखिर हम सब इन्सान हैं, फरिश्ते नहीं। मैं एक चीज का विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे सीने में दिल है और उस दिल में है गरीबों की बहतरी के लिये एक कसक। जनसेवा किसी एक अंग की ठेकेदारी नहीं है। जितनी जनसेवा आप और हमसे हो सकती है, हमें करनी चाहिये। छोटी छोटी छिद्रान्वेषी बातों को बढ़ा कर विरोध और झगड़े की नीति को भुला देना चाहिये और मुल्क की बहतरी के लिये मिलजुल कर काम करना चाहिये और घाटे को दूर करने के लिये क्या क्या काम करने चाहिये इस पर भी विचार करना चाहिये। मैं एक और चीज की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि बिगड़ी हुई इस दशा को सुधारने के लिये हमें क्या क्या प्रयत्न करने चाहिये और बजट के घाटे को दूर करने के लिये क्या काम करना चाहिये। कल के वक्ताओं ने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि सरकारी काम में फिजूल खर्चा जहां जहां होता है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। कुछ ऐसे महकमें हैं जिनसे मुल्क की कुछ भी सेवा नहीं हो सकती है; जैसे प्रोक्योरमेन्ट सिविल सप्लाइज का महकमा इत्यादि; जो जनता के हितों के लिये कायम किया गया था, उन्हें हटा दिया जाय। जहां तक इन महकमों की कारगुजारी देखी गई है मेरे ख्याल से किसी भी सदस्य को यह कहने में संकोच नहीं होगा कि भ्रष्टाचार को बढावा देने में कहां तक ये महकमे सहायक हुए हैं।

श्री गोपीलाल यादवः-माननीय अध्यक्ष, मैं यह चाहता था कि अपने मित्र श्री नाथूरामजी मिर्धा को इस बजट पर बधाई देता;लेकिन मैंने जितनी दफा इस बजट को इन दो दिनों के अन्दर देखने की कोशिश की मुझे सिवाय निराशा के कोई और बात नजर नहीं आई। मैं यह कह सकता हूं कि इस बजट की विशेषतायें जो मैं देख सका, वह साफ है। उनमें सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यह एक वेल फेयर(जन हितकारी) बजट नहीं है। यह एक पुलिस राज्य का बजट है जो कि विदेशी हकूमत के ढांचे पर बनाया गया है। मैं आपको दूसरी बात यह बता देना चाहता हूं कि हमारे राजप्रमुख ने अपने भाषण में यह बताया था कि हमारा उद्देश्य एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है। हमारा विधान यह कहता है कि हम कोओपरेटिव कॉमनवेल्थ की स्थापना अपने देश में करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस बजट में कोओपरेटिव कॉमनवेल्थ की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस बजट को देखने से एक बात भी ऐसी नहीं मिलेगी कि जो हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ जा रहा हो। हम वर्गविहीन समाज की स्थापना कर सकें या कोओपरेटिव कॉमनवेल्थ की स्थापना

अपने देश में कर सकें । तीसरी विशेषता यह है कि यह बजट सिर्फ शहरियों को खुश करने वाला बजट ह । इसमें देहातों की ९० फी सदी जनता की भलाई के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयत्न की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । चौथी विशेषता जो मुझे इस बजट में नजर आती है वह यह कि हमारी सरकार के कंधे कमजोर हैं जो कि अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हैं और सेंट्रल से दिए गए आश्वासनों और कर्त्तव्यों को पूरा कराने की क्षमता नहीं रखता । पांचवीं बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इसको फरजी तौर पर घाटे का बजट बताया गया है; ताकि नये करों का बोझ जो गरीब जनता पर लादा जाय उसके लिए इस सदन की स्वीकृति प्राप्त कर लें और जो वायदे हमने गरीब जनता से किए थे कि तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे उसके लिए हम खामोश रहें । छठी विशेषता जो इस बजट की मैं समझ सका हूं वह यह है कि यह बजट एक ऐसा नाबालिग का बजट है जिसका मुनीम किसी दूसरी दुकान का एजेंट है । सातवीं विशेषता इस बजट की है वह यह है कि यह एक पुरानी नकल है इसमें कोई नवीनता नहीं है; मौलिकता और क्रांतिकारी भावना का बिलकुल अभाव है । इसके अलावा मुझे और कोई उम्मीद इस बजट से नहीं दिखलाई दी । मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य मेरे वित मंत्री या गवर्नमेन्ट के दूसरे मंत्रियों पर आक्षेप लगाने का नहीं है बल्कि उनको उस मार्ग को दिखाना है जो कि उनके विधान में बताया गया है और जो कांग्रेस के विधान में भी बताया गया है ।

मैं यह पूछना चाहता हूं की हमने वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए क्या किया क्या हमने ऐसे टक्स लगाए जिससे मालदारों से रुपया वसूल करके गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके । इनमें देखने में आता है कि गरीबों की कमर जो करों के बोझ से टूटी जा रही है वहां उस पर और टैक्स लगाने के लिए सोच रहे हैं वहां उन मालदारों पर जो कि शासन व्यवस्था की तरफ एक पैसा भी नहीं देते या बहुत कम देते हैं उनसे और रुपया लेने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरी धारणा के अनुसार एक राष्ट्र का बजट एक पारिवारिक बजट के रुप में होना चाहिए । एक परिवार के अन्दर कई प्रकार के आदमी होते हैं, एक अधिक कमाता है तो दूसरा कम भी कमाता है। लेकिन वहां सबको एक सा खाना मिलता है, सबको एक से वस्त्र मिलते हैं, सबको एक समान रहने, खाने पीने, शादी-विवाह, शिक्षा आदि पर व्यय होता है। लेकिन इस बजट के अन्दर कौटुम्बिक भावना का बिल्कुल अभाव है और जब तक यह चीज हमारे अन्दर नहीं आई तो हम अपने देश का उत्थान नहीं कर सकते । मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे विधान में यह साफ है कि हरेक देश के बच्चे २ को समानता का अधिकार है, क्या हमने कोई कदम उन गरीब बच्चों के लिए उठाया, जिन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलने की वजह से शरीर गल जाते हैं? क्या उस ओर कुछ किया गया।

गरीबों के पास पैसा नहीं होने से उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। मालदारों के बच्चों के समान उन्हें अवसर की समानता देने के लिए

क्या हमने कुछ उपाय किए हैं ? अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो यह बजट किसी काम का नहीं । मैं आपको यह बतलाऊं कि इस बजट में जो घाटा दिखलाया गया है, मेरे मित्र कल से यह बतला रहे हैं कि यह घाटा किस वजह से हुआ । मैं तो यह कहने जा रहा हूं कि बजट में घाटा है ही नहीं । यह तो एक सर्प्लस बजट है और इसको और भी सर्प्लस बनाया जा सकता है । किसी भी मद में १०-२० लाख रुपया दिखाकर घाटे का बजट दिखाया जा सकता है । मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि पुलिस के बजट में सन् ५०-५१ में २,१७,००,००० रुपया सन् ५१-५२ के रिवाइज्ड बजट में २,५०,००,००० का है । और ५२-५३ में २,८०,००,००० कर दिया । यह बढावा ३०,००,००० का क्यों कर दिया गया अगर हम इसको न बढावें तो हम २० लाख की बचत कर सकते हैं । इसके साथ ही हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया कि ५० लाख रुपया हमें बोर्डर पुलिस पर खर्च करना पड़ता है, मैं यह कहता हूं कि बोर्डर पुलिस का खर्च करना हमारा काम नहीं है, यह सारा बोझा सेंट्रल पर होना चाहिए । यहां पर पहले भी युनाइटेड इंडिया था उस समय भी इस पर खर्चा होता था; पर वह सेंट्रल से मिलता था । आज भी हमको मिल सकता है, अगर गवर्नमेन्ट सेंट्रल के सामने इस चीज को रखे । लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह कमजोरी गवर्नमेन्ट की है । इसके बजट को बनाने वाले मुनीम चाहे दूसरी दुकान के एजेंट हों उनसे मेरा तात्पर्य यह है कि जिन लोगों के हाथ से यह बजट बना है उनमें सेंट्रल गवर्नमेन्ट का ज्यादा हाथ है न कि राजस्थान गवर्नमेन्ट का । वे ज्यादा बोझ अपने सिर पर लेना नहीं चाहते, वे तो चाहते हैं कि ज्यादातर बोझ राजस्थान गवर्नमेन्ट पर ही पड़े । कोई कारण नहीं, अध्यक्ष महोदय की हम इस कदर अपने बोझ से दबे चले जायं और सेंट्रल गवर्नमेन्ट अपने आश्वासन पूरे नहीं करे । वित्त मंत्री महोदय ने कहां है कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट से ४ करोड़ रुपये देने का आश्वासन मिला था लेकिन उसे पूरा नहीं किया । जिस वक्त यह आश्वासन दिए गए उसके बाद कई गवर्नमेन्ट यहां पर कायम हुई; वह इस किस्म की थी कि वह सेंट्रल गवर्नमेन्ट से इस बात पर कोई झगड़ा नहीं कर सकती थी और यही कारण था कि हमको कुछ भी नहीं मिला । इसके बाद मैं दूसरी बात यह बता देना चाहता हूं कि इस बजट में १७ लाख की नये कस्बों में बिजली की योजना है ।

कल कुछ लोगों ने बतलाया कि बिजली के तमाम कामों में घाटा हुआ है । यदि हम सारे बजट में से देहाती लोगों के लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो हम केवल १० कस्बों के अन्दर, ५ कस्बों के अन्दर बिजली के एन्जिन लगा दें तो इस देश का भला होने वाला नहीं है, उसके लिए हम एक दो साल ठहर सकते हैं । इससे १७ लाख की फिजूल मद खाली होती है । उन रुपयों की बचत हो सकती ह ।

इसके साथ चम्बल योजना है जिसकी देखभाल, जांच पड़ताल करने के लिए ७ लाख रुपये रखे गये हैं । जहां कि यह जो हमारा लेजिस्लेचर

है, जिसमें कि १६० सदस्य हैं, जिसका इतना बड़ा सेक्रेटेरियट है उसका बजट भी ७ लाख का है तो एकाध एन्जीनियर जाकर चम्बल योजना की देखभाल करे उसके लिए ७ लाख रुपयों का प्रोवीजन कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह सब देखभाल का काम सेन्टर (केन्द्र) का होना चाहिए। यदि इसे हमारे बजट में रखा ही जाय तो इस पर काफी खर्चा हो चुका है। इस पर ५० हजार या १ लाख से ज्यादा रुपयों की जरुरत नहीं है।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं वह यह है कि पिछले साल ५० लाख रुपये कान्टिजेन्सी फन्ड में रखे गये थे; जिसमें से एक पैसा भी बजट में खर्च नहीं हुआ। इस साल वह नहीं रखे गये हैं यह ठीक ही है; लेकिन उन ५० लाख रुपयों में से फिर इस साल ले सकते थे, यदि इतने नहीं तो कम से कम २५ लाख रुपये रख लिये जाते। इस तरह से कई मदें ऐसी हैं जिनमें फिजूल रुपया दिखला दिया गया है।

मैं आपको बतलाऊं कि भाखरा नांगल योजना है, जिस पर कि ८२ लाख रुपये इस साल खर्च में दिखला दिये हैं। इस साल ८२ लाख रुपये खर्च होना नामुमकिन है। ज्यादा से ज्यादा २०, ३० या, ४० लाख रुपये खर्च इस साल में हो सकते हैं। इस साल केवल ४० लाख दिखलाना चाहिये; न कि ८२ लाख। इस तरह से मैंने हिसाब लगाया तो २ करोड़ रुपये फिजूल में इधर उधर डाला हुआ पाया। इस तरह से यह जो ९३॥ लाख के घाटे का बजट है वह १ करोड़ से ऊपर का सरप्लस का यह बजट बनाया जा सकता है। सेन्टर से भी कई वायदे पूरे कराने होगें। यही नहीं बल्कि जो हमारा ड्यू है वह भी ले सकें। उनके द्वारा इनकम टैक्स लगाया हुआ है। उस इनकम टैक्स में हरेक प्रान्त का हिस्सा है। जो हमारी स्टेटों की रेलें उन्होंने ले ली हैं जिन पर कि हमारा केपिटल आउट-ले हुआ है उसको मीट करने के लिए इसमें कुछ नहीं दिया गया है। दूसरी चीजें जिसके लिए हम ले सकते हैं वह है एक्स्पोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज जो सेन्टर लेती है। यह माना कि सेन्टर देश का काम चलाती है, उसको रुपयों की जरूरत होती है किन्तु उसकी बचत में से हिस्सा लेने का अधिकार हम सबको होता है। इसके लिए ठीक ढंग से हमारी मांग रखी जानी चाहिए; सेन्ट्रर के सामने।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक छोटी सी बात बतलाना चाहता हूं कि फूड में जितने रुपये लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत कुछ रकम वेस्ट हो रही है। ऐसे मामले इस तरह से टेकल नहीं किये जाने चाहिए थे। देश में इतनी अन्न की कमी नहीं है जितना कि उसको दिखाया जा रहा है। जो कुछ कमी हो रही है वह हमारी वजह से है। मुझे एक चीज याद आगई है कि गई लड़ाई के वक्त, यानी सेकन्ड वर्ल्ड वार (द्वितीय विश्वयुद्ध) के समय में हमारे यहां रेजगारी की कमी हो गई थी, किसी को रेजगारी नहीं मिलती थी। रेजगारी देश में मिलती थी, किन्तु लोगों को डर था कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट तो खत्म होने वाली है इसलिए नोट तो खत्म हो जायेगें तो रेजगारी होगी तो यह पैसे ही बचेगें। तो जिस किसी के पास रेजगारी थी उन्होंने उसे अपनी जेब में रख ली। नतीजा यह हुआ कि

रेजगारी मिलना बन्द हो गया। इसी प्रकार यह फूड का मसला है। हमने कई अखबारों में देखा है कि हमारे देश में फूड नहीं है। नतीजा इसका यह हुआ कि लोगों के अन्दर होर्डिंग, (इकट्ठा करने) की आदत पैदा होगई। जो आदमी अनाज पैदा करते हैं वह सोचते हैं कि रेडियो में सुना था, अखबारों में पढ़ा था कि फूड की कमी है, आगे क्या होगा, देश में अन्न खत्म हो जायगा और इस अन्देशे से वह बाजार मे अनाज नहीं लाता है और अपने घर में ही रख लेता है। कन्ज्युमर भी जहां एक महिने का अनाज खरीदने जाता है तो १ वर्ष या ६ महीने का रख लेता है कि बाद में मिले या नहीं मिले। वह साल भर का २ साल का खरीद कर अपने घर में जमा कर लेता है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेन्ट है कि इस डर से कि कहीं राजस्थान भूखों नहीं मर जाय; बड़े २ गोदामों में जिन पर कि कई करोड़ों रुपये खर्च कर दिये हैं, गोदामों में अनाज भर देती है। इसके बाद सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट भी यह सोचती है और जहां कहीं से बाहर से या देश में से अनाज लेकर बड़े २ गोदामों में होर्ड (इकट्ठा) करती है तो इस तरह से कन्ज्युमर, प्रोडयुसर, स्टेट गवर्नमेन्ट, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट, सब इस अनाज के होर्डिंग में लगे हुए हैं, और यही इस अनाज की कमी का मुख्य कारण है। आज इस होर्डिंग को बन्द कर देवें, स्टेट गवर्नमेन्ट बन्द कर दें, कन्ज्युमर और प्रोडयूसर बन्द करें तो मैं समझता हूं कि अनाज की इतनी बड़ी कमी हमारे यहां है नहीं। अनाज को इकट्ठा करने में जिस कदर रुपया लगाया जाता है, यद्यपि यह खर्च नहीं है, लोगों को तकलीफ दी जाती है वह आवश्यक नहीं है, वह मुनासिब नहीं है। हमारी स्टेट का भी बहुत सारा रुपया इस अनाज के खर्च में फसा हुआ है, वह कोई खर्च की चीज नहीं है लेकिन हम उस रुपये को फंसा रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वह है कस्टम्स के सम्बन्ध में। किसानों पर इस वक्त इतना बोझ टेक्सेशन (करों) का है, जिसका अन्दाजा आप को थोड़े से शब्दों में बताना चाहता हूं। वह अपने एक खेत में काफी महनत करके सरसों पैदा करता है। उसने ५ बीघा सरसों बोई तो ४ मण फी बीघे के हिसाब से सरसों २० मण पैदा होगई। यदि हम उसे बाहर भेजें तो २।।) रु० मण टेक्स लेते हैं। आज कल सरसों का भाव १५) रु० या १२) रु० मन है। इस हिसाब से वह सरसों २५०) रु० उसमें से १५०) रु० तो जुताई वगैरह में लग जाते हैं और केवल १००) उसको उसकी मेहनत के मिलते हैं। उन १००) रुपयों में से ५०) टेक्स के रूप मे सरकार ले लेती है। इसी तरह से वह अपने खेत में गेहूं बोता है। उसके पांच बीघे के खेत पर हम २ या १।। मण फी बीघा के हिसाब से ५ बीघों पर ७, ८ मन गेहूं लेवी में ले लेना चाहते हैं। उस लेवी में लिये जाने वाले गेहूं को अगर बाजार में २०) रु० मन का भाव है तो हम १६) रु० मण में ही लेना चाहते हैं। ४) रु० मन का घाटा देकर उससे हम ८०) रु० ले लेना चाहते हैं। इसी तरह ३-४ साल महनत करके वह बछड़े को तैयार करता है और उस पर करीब करीब १००) रु० खर्च करता है और उतने में ही वह बिका है। अगर वह बाहर जाय तो उस पर भी हम १५,) २०) रुपये का टेक्स ले लेना चाहते है। यदि एक किसान की आमदनी हम २००) रुपये मानें तो दो हजार में से कम से कम ५००) रुपये का टेक्स उनको देना पड़ता है, यानी आमदनी का २५ प्रतिशत, उस गरीब

किसान से टेक्स में वसूल कर लिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि उस गरीब किसान के अलावा उन लोगों से जिनके पास सैकड़ों मकान हैं, सैकड़ों दुकानें है, जो कई हजार रुपये माहवार का रेन्ट (किराया) लेते है और जिनकी मिलें है लाखों रुपयों की, उन से २५ प्रतिशत उनकी आमदनी का आप टेक्स ले लें तो आपकी तमाम दिक्कतें मिट जायं । लेकिन उनकी तरफ आपका बिलकुल ध्यान नहीं हैं ।

इस के बाद इस बजट में एक बहुत इम्पोर्टेन्ट बात है और जिसकी वजह से इस पर क्या असर आता है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं; वह है जागीरी समस्या । इसमें कुछ सजेशन्स बताना चाहता हूं । मेरा ख्याल है कि हमारा मतलब पेड़ गिनने से नहीं है मगर आम खाने से है । यह जो जागीर एबोलिशन शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है और अगर हम नहीं करें तो हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं हैं । हम तो यह जानते हैं कि वहां का जो किसान है उसको राज्य की ओर से कोई राहत मिली हो । किसानों को फिक्सिटी आफ स्टेट और सिक्यूरिटी आफ टेन्योर मिला है या नहीं; यह हमारा काम है । गवर्नमेन्ट ने इसकी तरफ कुछ कदम उठाये हैं । बेदखलियां बन्द कर दी हैं । बंटाई की तरफ भी ध्यान दिया है; यह प्रशंसनीय चीज है । लेकिन मैं अब दूसरी चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज उसका संबन्ध राज्य के किसी से भी हो कि आज जागीरों को लेने की स्थिति में नहीं हैं क्यों कि आपने अभी कहा है कि उनका सेटलमेन्ट करना है । मैं तो यह कहना चाहता हूं मेरी जागीरदारों से भी बातें हुई है। जागीरदार सब इस बात को जानते है कि उनकी जो आमदनी है उसका कुछ हिस्सा शिक्षा में, कुछ हिस्सा पुलिस में, उसका कुछ हिस्सा सडकों पर, कुछ हिस्सा अस्पताल में खर्च होना चाहिए और वह उसमें कन्ट्रिब्यूट करने को तैयार भी होंगे । अगर कोई गवर्नमेन्ट की तरफ से जागीरदारों से बातचीत करे । मैं नहीं समझता हूं कि जागीरों की आमदनी कितनी है जो कि ५ हजार से ऊपर की है, लेकिन मेरा खयाल है कि जागीरदारों के पास उनके खर्चे के लिए मिनिमम (कम से कम) ५ हजार रुपये रख लिए जांय और मेक्जिमम (ज्यादा से ज्यादा) ५० हजार रुपये छोड़ दिये जायं और बाकी आमदनी जो जागीरों की है वह पुलिस, शिक्षा, अस्पताल और दूसरे कार्यों के लिए जो कि उनको कन्ट्रिब्यूट करना चाहिये उनसे ले लिये जायं; तो कम से कम ३-४ करोड़ रुपयों की इस तरह से आमदनी हो सकती है। और इसी तरह ३-४ करोड़ स्टेट मालदारों से ले सकती है और इस प्रकार हम इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर सकते हैं जिससे कि हम किसानों का भला कर सकें।

इसके अलावा कई बड़ी योजानायें बना रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा । अगर हम १० करोड़ रुपया भी कुओं के लिए रख दें तो कई ज्यादा किसानों की भलाई कर सकते हैं और ज्यादा अन्न पैदा कर सकते हैं । हमारे पिछले तीन सालों में, मैं जिस जिले से यहां चुनकर आया हूं, मेरे जिले में एक भी कुंआ नहीं बना । गवर्नमेन्ट की तरफ से बहुत तकाबियां कल्टिवेशन के लिए दी गई हैं । लाखों की तादाद में रुपया ट्रेक्टरों

की खरीद के लिए दिया गया है। २५ हजार में एक ट्रेक्टर आता हैं उसका आधा यानि १२ हजार रुपया सरकार दे देती है । यह सब मालदार लोगों को मालदार बनाने के लिए किया गया है। कुंओं के लिए तकाबी नहीं । हर डिस्ट्रिक्ट में यदि १० लाख रुपया कुओं पर हम खर्च कर दें तो २४ डिस्ट्रिक्टों में दो तीन करोड़ रुपया काफी होगा। इसका यदि हम सालाना प्रोवीजन रख दें तो चार पांच साल के अन्दर गांवों में इतने ज्यादा कुंए बन सकते हैं जिससे गांवों की अनाज की स्थिति, अनाज की समस्या का हल हो सकता है । गांवों के किसानों की गरीबी मिट सकती है । यदि हम गरीब किसानों की तरक्की की और ध्यान नहीं देते तो देश की उन्नति नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, इन थोड़ी बातों से मैं आपको बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्चा है वह बहुत ज्यादा है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिये । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम सब को समान अवसर दें गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाये, मालदारों को नीचा लायें, इस तरह से धीरे धीरे हम सब को समान स्तर पर ला दें । जब तक बजट में इसके लिए प्रोविजन नहीं मैं यही कहूंगा कि यह बजट बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है । मेरा अनुमान है कि जब तक हम लोग साथ मिलकर एक कोओपरेटिव कोमनवेल्थ व क्लासलेस सोसायटी का बजट बनाने को तैयार होंगे, नये सिरे से तभी हम हमारे प्रान्त की गरीबी को दूर कर सकेंगे और जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे ।

श्री मथुरादास माथुरः—माननीय अध्यक्ष जी, दो दिन पूर्व वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया उस पर इस सदन में बहस चल रही है । विरोधी दल के कई साथियों ने इस बजट के पक्ष तथा विपक्ष में प्रकाश डाला है । इस बजट को देखने से एक ऐसा अनुमान होता है कि वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह ऐसा बजट है जो इसी सदन के इस तरफ और उस तरफ को बैठने वाले सभी साथियों को इस में सन्तोष नहीं। पहले हम इस बजट के अलग अलग आंकड़ों में जायं तो हमें सोचना है कि इसका क्या कारण है । कुछ महीने हुए हमारे सदन के विरोधी पक्ष के नेता इसी राजस्थान सरकार के मंत्री थे, इसलिये वे मेरे साथ इस बात को महसूस करेंगे कि जो ५१-५२ का बजट, जिस वक्त विधान सभा नहीं थीं, फिर भी आम जनता के सामने वह बजट रखा गया था, आप और हम सबने पढ़ा भी । वह बजट और उसके आंकड़े अखबारों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये पूरी तरह निकला । उसमें दिलचस्पी रखने वाले साथियों ने उसे पढ़ा होगा । जब से राजस्थान बना है तभी से उन आंकड़ों को सामने रख कर यदि हम देखें तो हमें यह बात मालूम होगी कि उस बजट में कोई है क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं दिखाई देता । इसलिये हमारे सदस्य यदि यह कहें कि हमारे आगे सरकार में जो सफेद टोपी वाले बैठे हैं उन्होंने बजट ठीक नहीं बनाया तो मैं यह कहूंगा कि हमने तो विरोधी दल के नेता को भी बजट बनाने का मौका दिया था फिर भी उस बजट में सिद्धान्तिक अन्तर नजर नहीं आता ।

श्री गोपीलाल यादवः-ओन दी पाइन्ट आफ आर्डर सर, उस वक्त के विरोधी दल के वे नेता नहीं थे (हर्ष ध्वनि) ।

श्री मथुरादास माथुरः-मुझे समझ में नहीं आता कि विरोधी दल के नेता बनने से क्या उनके दिमाग में कोई खास परिवर्तन आ गया है या उस वक्त उनकी सरकार चलाने में दिलचस्पी नहीं थी। विरोधी दल के नेता होने से क्या किसी व्यक्ति में कोई परिवर्तन आ जाता है ? मैं तो यह महसूस नहीं करता । उन्होंने उस वक्त इमानदारी के साथ राज्य शासन के लिए काम किया था तो उस वक्त दल के नेता ने कोई ऐसी बात क्यों नहीं कही। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो बजट हमने राजस्थान बनने के शुरू से देखा उसमें और जो बजट हमारे सामने पेश है उसमें कोई अन्तर नजर नहीं आता। कुछ लाख रुपये एक सीगे से दूसरे सीगे में चले गये हैं; मगर यह बजट सर्विस क्लास (नौकरशाही) का बजट है जो सन् ५० से आज तक वैसी ही शक्ल का है; यही हमें नजर आता है। इसलिये आज दोष किसको दिया जाय? इस बजट के बनने से पहले संविधान की धारा ३७१ पर गौर किया गया। उसमें भारत सरकार के "ब" श्रेणी के जो राज्य हैं और उनके शासन को चलाने के लिए अधिकार जो मिले हुए हैं। यही बातें इस राज्य में भी हैं विरोधी दल के नेता भी इस बात को मन्जूर करेंगे कि राजस्थान सरकार के इस बजट की, इस सदन के सामने आने से पहले, जांच भारत सरकार ने हर नुक्ते निगाह से कर ली है।

आज राजस्थान सरकार का बजट इस सदन के सामने रखा गया है: सदन की राय के लिए। इसके साथ साथ ३७१ धारा के चलन की वजह से सरविस क्लास का इसमें हाथ लगा हुआ है। ऐसी शक्ल में यह हमारे सामने पेश हुआ है। हाउस के प्रतिगामी सदस्यों का इससे संतोष हो सकता है किन्तु प्रगतिशील विचारों के व्यक्तियों को इससे कभी सन्तुष्टि नहीं हो सकती। बजट की यह शक्ल जो हमारे सामने है उसकी एकमात्र वजह यह है कि यह बजट हम जिस प्रकार बनाना चाहते हैं, नहीं कर पाये हैं। इस बजट पर यदि गौर किया जाय तो इस बजट के अन्दर हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि काफी पैसा नौकरशाही में खर्च किया गया है। किसी भी बजट के सीगे को देख लीजिये उसका बहुत ज्यादा पैसा तनखा की मद में खर्च होता है। यह मानता हूं कि इस बजट को ठीक करने के लिए हमारे यहां पर बड़े तनखा पाने वाले लोग रखे गये हैं; उनको हम नहीं चाहते हैं। हमारे न चाहने पर भी, न चाहते हुए भी, वैसे काफी तादाद में लोग हैं जिनको, हमारे राजस्थान की आर्थिक हालत देखने से ज्ञात होता है कि वे हमारे लिए एक प्रकार की लग्जरी–है। इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सरविस (भारत प्रशासन सेवा), इन्डियन पुलिस सरविस (भारत पुलिस सेवा) में राजस्थान से भी व्यक्तियों को लिया गया है। वहां के लोग भी यहां आयेंगे, यहां के वहां जायगे। उनके हिस्से की छोड़ते हुए हमारे यहां काफी लोग ऐसे हैं जिनको हमारे माननीय मिनिस्टरों से दुगुना तिगुना वेतन मिलता है। राजस्थान की सुख–समृद्धि में यदि वे सहायक हों तो ठीक है लेकिन वे, हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, हमारे लिये लग्जरी बन जाते हैं। इसलिये अगर इस बजट को सुधारने के दो तरीके हो सकते है तो एक तो यह कि हम आमदनी को बढायें और खर्च को कम करें। जिनको ज्यादा वेतन मिलता है उसमें कमी की जाय। थोड़ी तनखा में यदि वे काम करने के लिए तैयार नहीं हों तो, भले ही वे कितने ही लाभदायी हों, हमारे प्रान्त के पास

पैसा न होने के कारण रखे नहीं जा सकते। इसके साथ साथ में आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि सदन के इस पक्ष के सदस्य और उस पक्ष के सदस्य दोनों तरफ बैठने वाले, सभी, इस बात का प्रयत्न करें कि धारा ३७१ को राजस्थान में लागू न किया जाय जब यह धारा राजस्थान पर लागू नहीं रहेगी तभी सही माने में हमारा बजट सदन के सामने आजाद रूप से पेश हो सकेगा और तभी सही तरीके से और आजादी से हम उसे अच्छा या बुरा कह सकेंगे।

इसके साथ साथ अभी मेरे किसी साथी ने यह कहा है कि जो बजट रखा गया है वह सिर्फ पुलिस बजट ही है। मैं यह कहूंगा कि मौजूदा देश की लॉलेसनेस (अव्यवस्था) की हालत को देखते हुए यदि हमारे लॉ एन्ड ओर्डर के मिनिस्टर (कानून तथा व्यवस्था के मंत्री) इस देश में फैली हुई लॉलेसनेस (अव्यवस्था) को मिटाने के लिये यदि इस बात की मांग करें कि हमको इससे भी (चीअर्स) ज्यादा पैसा मिले तो मेरा खयाल है कि शायद ही कोई सदन का सदस्य इस बात को नामंजूर करेगा। सदन के सभी सदस्यों को मालम ही होगा कि जोधपुर डिविजन में रहने वाले लोगों की क्या हालत है? क्या इस पक्ष के और क्या उस पक्ष के सभी को यह बात विदित ही होगा कि वहां आज से ३-४ महिनों से क्या हाल हो रहा है। वहां की परिस्थिति कितनी बिगड़ रही है। हर आलटरनेट डे (अवान्तर दिन) पर वहां एक डाका और चोरी होती रहती है। हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि इस लॉलेसनेस (अव्यवस्था) की स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार मदद दे। सरकार भी यही चाहती है कि इस चीज को खत्म करने के लिये जल्दी से जल्दी कदम उ ाये जावें; जिससे राजस्थान समृद्धिशाली बने और यहां पर अमन चैन कायम रहे। इस तरह से हम सभी लोग यही चाहते हैं। राजस्थान के बारे में अखबारों में इस प्रकार के समाचार आते हैं और लेख निकलते हैं। मैं उनका जिक्र करके आपका समय लेना उचित नहीं समझता मगर वे लोग यह कहते हैं कि राजस्थान की पुलिस थोड़ी है और उनके पास पूरे हथियार नहीं, इसलिये वह कुछ नहीं कर सकती। यह सुनना हम नहीं चाहते। इसलिये मैं सदन के सभी सदस्यों से, माननीय अध्यक्ष, आपकी मारफत सरकार को यह बता देना चाहता हूं की अगर वे दूसरी बातें जो जनता के हित की हों थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और पहले इस चीज को पूरा करें जो अति-आवश्यक है तो यह प्रान्त के हित के लिए अच्छी बात होगी। सडकें, होस्पिटल, स्कूलें आदि जो इतने अरसे तक नहीं थे एक साल और नहीं हों तो कोई नुकसान की बात नहीं। यों तो सभी चीजें जो जनता के हित की हैं होनी चाहिये। यह चीजें तभी हो सकती है जब हम सब अमन चेन में हों। मैं यह कहूंगा कि चंद स्कूलें जो खुलनी हैं न खुलें, चन्द सड़कें भले ही न बनें मगर यह सवाल लॉ एन्ड ओर्डर (कानून तथा व्यवस्था) का जो हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल है सबसे पहले हल होना चाहिये। इससे हम हिन्दुस्तान

के दूसरे रजवाड़ों के सामने अपना सिर, जिसे नीचे रखना पड़ता है, न रखना पड़ेगा । आज हम लोगों का मुल्क राजस्थान डकैतों का मुल्क कहा जाता है। एक दम यदि लाखों रुपये नहीं दिये जा सकते तो पी० डब्ल्यू०, शिक्षा आदि से १० हजार रुपये निकाले जा सकते हैं और लॉ एन्ड ओर्डर मेन्टेन (कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने) करने के लिये हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं; जिससे कि हमारा यहां लॉ एन्ड ओर्डर (कानून तथा व्यवस्था) कायम हो सके और हमारे मुल्क, जो डकैतों का मुल्क कहलाता है, न कहावे । आप काफी देख चुके हैं कि जो लोग हमारे यहां गांवों में रहते थे वे गांवों को, डकैतियों के कारण, छोड़ छोड़ कर परदेश और शहरों में आ गये हैं । आप देखेंगे कि जो गोडवाड़ के रहने वाले थे, बम्बई और अहमदाबाद आदि जा रहे हैं । यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है । इसमें राजस्थान की शान का सवाल है । यदि यह लॉ एन्ड ओर्डर (कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने) के लिये पुलिस बजट भी बन जाए तो हम उसको भी सहन कर लेंगे मगर हम यह चाहेंगे कि हमारे देश में लॉ एन्ड ओर्डर (कानून तथा व्यवस्था) कायम रहे। मेरा खयाल है कि मेरे सभी साथी इस सम्बन्ध में एक मत होंगे कि इस तरह से इस बजट को क्रिटिसाइज (आलोचना) नहीं किया जावे। मगर करोड़ों रुपये खर्च होंगे तो हम करें; मगर देश में चैन रखेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की भी, रियासतों की सुचारू रूप से चलाने की जवाबदारी है। क्या यह जवाबदारी एडवाइजरों और कौंसलरों को भेजने से पूरी हो जाती है? भारत सरकार यह सोचती होगी कि इस राजस्थान को अच्छे ढंग से चलाने के लिये व जनता में, जो इन्टिग्रेशन (एकीकरण) हुआ है इसके लिये विश्वास पैदा करने के लिये भारत सरकार काफी तादाद में मदद दें । ठीक है मगर इसके लिये में राजस्थान सरकार से व अपने सभी साथियों से यह कहूंगा कि वे भारत सरकार से अर्ज करें और जल्दी से जल्दी जोर डालें कि हमारा देश गरीब देश है इसलिये जितनी ज्यादा तादाद में भारत सरकार मदद दे सके, दे । ८०० मील अनमार्कड बोर्डर (अचिन्हित सीमा प्रान्त) के इलाके की हिफाजत के लिये हमको लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं उसको भारत सरकार खासतौर से रुपया दे कर राजस्थान को समृद्धिशाली बनाए । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान जो "बी" स्टेट में है उसके साथ एक सौतेले बच्चे का सा बर्ताव किया गया है । प्लानिंग कमिशन (निर्माण आयोग) के अन्दर जो रूपया राजस्थान को मिला है, दूसरे राज्यों को देखने से पता चलता है कि जहां दूसरे राज्यों को ३८) रुपया पर केपीटा (प्रति व्यक्ति) मिला है । वहां राजस्थान को सिर्फ ९ रुपया पर केपीटा (प्रति व्यक्ति) मिला है । यह एक ऐसी चीज है जिससे हम कह सकते हैं कि हम ज्यादा के हकदार हैं क्योंकि यह हमारी बेबी स्टेट (बच्चा राज्य) है। बच्चे को बढाने के लिये भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिये । इसलिये मैं अपने साथियों से अर्ज करूंगा कि वे बहुत ज्यादा जोर दें कि वे प्लानिंग कमिशन (निर्माण आयोग) से लॉ एन्ड ओर्डर को मेन्टेन करने (कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने) के लिये रुपया फाइनेन्स इन्टीग्रेशन (अर्थ एकीकरण) के माफिक लाने का प्रयास करें।

इसके बाद हमारे यहां के कुछ मित्रों ने बजट पर जो चर्चा की है उस पर

भी कुछ कहूंगा। मेरे एक साथी ने यह कहा कि इस बजट को देखते हैं तो मालूम होता है कि यह एक निकम्मा बजट है। इसमें कई बातें रह गई हैं। मैंने भी देखा है, सुना है लेकिन मेरे साथियों ने कहा कि जब डिमान्ड्स (मांगें) रखी जावेंगी उस समय हमें उसके सम्बन्ध में विशेष अध्ययन करने का मौका मिलेगा। उस समय यही कहने को काफी होगा कि इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं; यह बजट निकम्मा है जैसा कि इधर उधर के साथियों ने बताया है। इसमें कुछ कमी जरूर है। मेरे एक मित्र ने शिक्षा के सम्बन्ध में कहा है कि कुछ काम नहीं होता है और जो कुछ काम होता है वह प्रचार के लिये होता है। इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इस बजट को आप गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहां का शिक्षा का बजट कई दूसरी "ए", "बी" श्रेणियों के राज्यों के बजट से कहीं ज्यादा अच्छा है।

वह हिन्दुस्तान की बड़ी से बड़ी रियासत से, जिसकी कि आमदनी हमारी आमदनी से चार पांच गुनी अधिक है, उसके परसेन्टेज (प्रतिशत) से कम नहीं है। लास्ट इयर (पिछले वर्ष) भी कुल आय का ११ या १२ परसेन्ट (प्रतिशत) शिक्षा विभाग के लिये रखा गया था। आज भी यही आंकड़ा नजर आता है १२ प्रतिशत रुपया राजस्थान में शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। आप इसका मुकाबला उन रियासतों से कर सकते हैं जो इतना ही खर्च शिक्षा पर करती है। शिक्षा के लिये २ करोड़ रुपयों का बजट है। यह कहना गलत है कि इस रुपये का दुरुपयोग किया जाता है। मैं यह मानता हूं कि जितना रुपया रखा जाता है सही माने में उसका उपयोग शतप्रतिशत नहीं होता। हमारे यहां शिक्षा का अभाव है इसलिये यह जरुरी है कि काफी रकम रखी जाय। परन्तु इसके साथ ही सरकार को कई और भी आवश्यक खर्च करने पड़ते हैं। बजट बनाते समय हमें हमारी आमदनी का ख्याल करना पड़ता है। यह कहना गलत है कि इन्टिग्रेशन (एकीकरण) के बाद कोई नई स्कूल या कालेज नहीं खोले गये। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। शायद उनको मालूम नहीं है कि एडल्ट एज्युकेशन (प्रौढ़ शिक्षा) का जो प्रचार हुआ है उसमें किन किन का पैसा खर्च हुआ है। उसमें सरकार का एक पैसा भी बेजा खर्च नहीं हुआ है। जो कुछ खर्च किया गया है वह जनता से चन्दा करके खर्च किया गया है। जितनी क्लासेज (कक्षायें) चलाई गई है व एडल्ट एज्युकेशन (प्रौढ़ शिक्षा) सप्ताह मनाये गये हैं वे सब चन्दों से हुवे हैं। लगभग ७०० क्लासें (कक्षायें) चलाई गई थीं। सेठ साहुकारों से व जनता से हमारे विद्यार्थियों तक ने चन्दा इकट्ठा किया है और वही पैसा खर्च किया गया है।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--सरकार के पास भी पैसा प्रजा से ही आता है।

श्री मथुरादास माथुरः--जी हां, प्रजा के पास से ही आता है। प्रजा से जिन्होंने लाखों रुपये कमाये हैं उनसे ही छीने गये हैं। जो पैसा मिलता है उसमें से एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं किया गया है। यह मैं मानता हूं कि एडल्ट एज्युकेशन (प्रौढ़ शिक्षा)

ऐक आन्दोलन है जिसके लिये प्रचार कराना जरूरी है । प्रचार सरकार के लिये नहीं बल्कि एडल्ट एज्युकेशन (प्रौढ़ शिक्षा) के लिये किया गया है । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कदम उठाया है उससे राजस्थान पीछे नहीं रहा है । यह आपने अखबारों में पढा होगा । जो एलाउन्स (भत्ते) टीचर्स (अध्यापकों) को इसके लिये दिया जाना तय हुआ है वही दिया जाता है। यह कहना कि एक्सप्लोइटेशन (शोषण) किया जाता है, गलत है। ७५००० आदमियों को इस तरह की शिक्षा दी गई है । डेढ़ करोड जनता को एडल्ट एज्युकेशन (प्रौढ़ शिक्षा) के लिये तैयार करने के लिये बहुत बड़े आन्दोलन की आवश्यकता पड़ती है । इसका नतीजा एक साल या दो साल में नहीं निकलता। भारत सरकार ने भी सात साल की अवधि रखी है कि इस अवधि में भारत में एक भी आदमी अनपढ़ न रहे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथी, चाहे वे इधर की बेंचों पर बैठे हों, या उधर बैठे हों अपने दिमाग का बैलेन्स (संतुलन) न खोएं। मैं इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रचार और आन्दोलन किया जा रहा है और जो स्वास्थ्य सप्ताह मनाये जाते हैं उनमें लगने वाला पैसा फिजूल खर्च नहीं किया जाता है । यह कहना है कि अब सफाखानों में बेन्डेज (पट्टियें) तक नहीं मिलती; गलत है। अलबत्ता यह बात तो जरूर है कि टेनिस खेलते अगर रगड आ गई तो पहले छः फुट की बेन्डेज बांध दी जाती थी; वह बात अब नहीं रही । लेकिन यह अर्ज करता हूं कि यहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्था किसी भी अन्य स्थान से कम नहीं है । आखिर हमारे विरोधी दल के नेता स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं उनसे कोई बात छिपी नहीं है । यह कहना कि बीकानेर से डाक्टर जयपुर चले गये हैं , जोधपुर से सामान चला गया है , वहां के अस्पताल खाली हो गये हैं ; मैं समझता हूं कि यहां आकर, कुछ न कुछ विरोध में कहना चाहिये, इसी गरज से यह बातें कही गई है । आप इतने उदार तो न बनिये। आप कहते हैं कि दवाइयें नहीं मिलती। डाक्टरों और नरसों को तनख्वाह बराबर नहीं मिलती । इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां नरसों आदि को जो तनख्वाह मिलती है वह स्टेन्डर्ड (प्रमाण) में हिन्दुस्तान के किसी भी स्थान से कम नहीं है । इसलिये कोई कमी तनखा में नहीं है । फिर भी यह प्रचार चलता है । कम से कम हाउस के सदस्यों को तो ऐसा नहीं मानना चाहिये । मैं मानता हूं कि इसमें और भी तरक्की की जरुरत है । उसके लिये हमारा फर्ज है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लगायें । लेकिन पैसा लाने का साधन जुटाना पड़ेगा । इसके साथ ही यह भी अर्ज करूंगा कि मुझे जिन्दगी में कई पुस्तकें पढ़ने और स्पीचें (व्याख्यान) सुनने के मौके मिले हैं । सिद्धांत के तौर पर एक चीज स्वीकार करनी पड़ेगी कि हिन्दुस्तान में कोई पार्टी शराब चालू रखने के लिये आन्दोलन नहीं करती । शराब खोरी ने कई लोगों का सत्यानाश किया है । यह चीज आपसे छिपी नहीं है । शराब पर कर लगाया जा रहा है । उसपर आप ऐतराज करें तो यह प्रतिगामियों का ऐतराज होगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सभी लोग इस मामले में एक हो जावें और हम इसे बंद करने की कोशिश करें । मैंने शिक्षा विभाग में हुक्म निकाला था कि इस डिपार्टमेन्ट का कोई अफसर (अधिकारी) शराब नहीं पीयेगा ।

श्री जसवन्तसिंह:—यह ओर्डर वापिस क्यों लिया गया ।

श्री मथुरादास माथुरः--मैं अर्ज करना चाहता हूं कि...........

(घंटी बजने से भाषण बन्द करना पड़ा)

श्री मोतीराम:--अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले इस बात का धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में प्रजातंत्र की स्थापना होने पर आज यह पहला बजट है। इस बजट को देखने के बाद मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मुझे एक चीज का खेद है कि इस बजट को रखते समय हमारे नेता ने बीकानेर डिविजन के साथ सौतेली मां का सा वर्ताव किया है। इसका कारण यह है कि बीकानेर ने एकीकरण के समय ५,००,००,०००) रुपये राजस्थान सरकार को दिये थे। इस तरह की आवाज हमारे सामने बैठने वाले मित्रों ने दी थी। ५००,००,०००) रुपये महाराजा ने राजस्थान को सौंपे थे; सिर्फ डेवलपमेंन्ट के लिये रखे गये थे। डेवलपमेन्ट का काम हो जाता तो रिजर्व में नहीं रहते। पहले गंगानगर में एक डिग्री कालेज खोलने का विचार था लेकिन राजस्थान के अन्दर बीकानेर रियासत मिल जाने के बाद इस तरह की चुप्पी पड़ी कि उसका कोई हवाला तक नहीं दिया गया। यह गंगानगर राजस्थान की एक नाक है और सब से ज्यादा कर वहां के लोग देते हैं। इसी गंगानगर में करनपुर और रायसिहनगर के लिये ४० लाख रुपया बीकानेर लोअर मिडिल वाटर वर्क्स के लिये रखे थे माननीय अध्यक्ष, क्या इसी बात पर डटे रहेंगे कि उस जिले पर कोई ध्यान नहीं दिया जाय।

चार साल तक इस जिले की जनता को यह आश्वासन दिलाते रहे कि कोई बात नहीं है। रियासतें मर्जर हो गई हैं--ये सारी बातें आयन्दा पूरी हो जाएंगी; यह बजट आने वाला है। इस बजट की ओर हम अपनी नजर दौड़ाये रखे थे और लोगों को यह दिलासा दिलाते रहे थे कि यह रकम आयेगी और आपकी सारी बातें पूरी की जायेगी; लेकिन आज मैं देखता हूं कि वहां के लिए एक भी चीज नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह है कि बीकानेर में एक ऐसा जमाना आया था कि एक रुपया मन अनाज जौ, चना बिका था और दो रुपये मन गेहूं बिका था। उस जमाने में बीकानेर गवर्नमेंट ने किसानों पर कर लगाये थे जिस वक्त कि वे कर नहीं ले सकते थे; तो सिर्फ ६ साला रकम और खाली रेट की बकाये और नजराने में खाते खारिज कर दिये गये थे; उस समय किसानों पर कर लगा कर रुपया वसूल किया गया था। ३७॥ रुपया; फी मुरब्बा लगाकर वसूल किया गया था इसलिये कि पुल वगैरा बना दिया जायगा। लोगों ने अपने घर के जेवर तक बेचकर यह कर चुकाया था जो आज क्या वह कर खाला पर अब तक पुलिये नहीं बनाई गई और इस बजट में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है इसलिये हमें खेद है कि हमारी तरफ क्या पीठ ही फेर ली है जब हमारे यहां कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात को गौर से देखे कि जिस जगह सड़कों की जरूरत नहीं वहां सड़कें जरूर बनावें। कई जगह सड़कों के न बनने की वजह से कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उसकी

हद नहीं है । राजस्थान का दूसरा हिस्सा जो सड़कों से छाया हुआ है और गंगानगर की तरफ जो एक सरसब्ज इलाका है उसमें सड़कों की निहायत जरूरत है ।

चौथी बात अर्ज करना चाहता हूं हम लोग बोर्डर पर रहने वाले हैं और पंजाब और पाकिस्तान की सरहद पर रहने वाले हैं तो हमारा पंजाब और पाकिस्तान से आने वाला माल हिन्दूमालकोट होकर ही गंगानगर पहुंचता है तो गेहूं और ट्रकों पर लाया जाता है तो हिन्दूमलकोट से जो गंगानगर तक सड़क है वह डॉंबर रोड बननी जरूरी है । इस बजट में इस सड़क का कोई जिक्र नहीं आया है । हमारे इलाके के अन्दर मेले आदि में जो माल की बिक्री होती है वह पंजाब के सिवाय कोई व्यापारी नहीं है । तो १५ रुपया कस्टम और एक आनी रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा लिया जाता है । तो इस तरह से किसान का एक अच्छा कस्टम और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ही पूरा हो जाता है । इसलिये कृपा करके कस्टम ड्यूटी जो है वह कम की जावे । और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे पांच करोड़ रुपये हैं जिसमें चालीस लाख वाटर वर्क्स गंगानगर, रायसिंहनगर और करनपुर के लिये थे और २ करोड़ खालों की पुलिया और सड़कों के लिए रखे गये थे वह रकम तो उसी इलाके के बजट में रखनी थी । लेकिन अफशोस है कि नहीं रखी गई । वहां की जनता का विश्वास इस बजट पर नहीं रहा और सरकार ने किसानों पर और कर लगाने के लिए १५ लाख रुपये रख दिये हैं। वहां तो पहले ही बहुत ज्यादा कर है । इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री बृजेन्द्रपालसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बड़े २ योग्य सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये । बजट का विषय गम्भीर तो है ही लेकिन इस वर्ष ९३,००,००० लाख रुपयों का घाटा बताकर उसको और भी गम्भीर बना दिया गया है । आमदनी का जरिया जो इस समय बजट में दिखाया गया है । पिछले साल के अंकों के आधार पर ही है इसको बढ़ाने के लिए हमको भरसक प्रयत्न और साधन करने होंगे । बजट का जो खर्च माननीय वित्त मंत्रीजी ने दिखाया है उसमें हमको, मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि उचित रूप से उसे खर्च करना चाहिए । मैं सदन का ध्यान मेरे क्षेत्र करौली की ओर दिलाना चाहता हूं । इस ४ साल के समय में करौली की जनता को घोर निराशा और दुखों का सामना करना पड़ा है । यह इलाका एक पहाड़ी और जंगली है। इसमें सड़कों इत्यादि का साधन नहीं है । भूतपूर्व सरकार ने जनता की सुविधा के लिए सड़कों व बान्धों का निर्माण कराया । लेकिन मुझे यह बड़े दुख के साथ सदन के सामने कहना पड़ता है कि नई सड़कों का निर्माण तो दूर रहा जो अधूरी सड़कें बनी हुई थी, बान्ध अधूरे पड़े हुए थे वह आज तक उसी हालत में पड़े हुए हैं । यहां तक कि बनी हुई सडकों पर मिट्टी तक भी सरकार नहीं डलवा सकी है और वहां का यह हाल हो गया है कि उन पर एक बैलगाड़ी का चलना भी मुश्किल हो गया है ।

करौली को एक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर न बनाकर एक सब-डिविजन बना

दिया गया है । सवाई माधोपुर जहां कि डि० हेडक्वार्टर के कोई साधन बिजली, मकान, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर सरकार ने लाखों रुपया खर्च करके और सुविधायें दी; जब कि करौली में एक पैसा भी सरकार को खर्च नहीं करना पड़ता और वहां पर सारी की सारी सुविधाएं मौजूद थी । लेकिन इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । इस वर्ष के बजट में तो सवाई माधोपुर के ऑफिसेज के लिये ७०,००० रुपया बजट में दिखाया गया है । अगर मैं निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर से डि० हैडक्वार्टर्स हटाकर करौली में कर दिया जाय तो ७०,००० रुपये की बचत हो सकती है बजट में । (करतल ध्वनि)

स्वास्थ्य की हालत तो और भी सोचनीय है । करौली का अस्पताल एक उच्चकोटि का स्थान राजस्थान में रखता है, जिसमें कि एक बहुत बड़े योग्य डाक्टर भी थे और जिसमें एक्सरे और आयिरन लंग आदि है उसको आज एक डिस्पेंसरी के रूप में बनाया जा रहा है । जनता को जो सुविधाएं पहले थी अब क्या वह इस प्रजातंत्र के शासन का यह सिद्धान्त है कि जो सुविधाएं जनता को पहले प्राप्त थीं वह उनसे छीन ली जाय ।

स्कूलों के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि करौली में एक हाई स्कूल है जो कि ६० वर्ष पहले स्थापित हुआ था । उसमें इस वक्त करीब ५०० विद्यार्थी हैं और इस वर्ष करीब ६० विद्यार्थी मेट्रिक्युलेशन एक्जामिनेशन में एपियर होगें (दसवीं कक्षा में बैठेंगे) । इस बात को देखते हुए वहां पर इन्टर कालेज की अत्यन्त आवश्यकता है । लेकिन हुआ यह है कि सरकार ने जो गंगापुर में, जहां कि एक वर्ष हुआ हाई स्कूल कायम हुआ ह, जिसको इन्टर कालेज बनाने का विचार किया है, तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इन्टर कालेज बनाने का यदि विचार हो तो इस बजट में करौली को प्रथम स्थान दिया जाय ।

खेती के बारे में इतना ही सदन के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि इस वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण सूखा पड़ने से किसानों के पास अनाज की कमी है, लेकिन सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उनसे उतना ही लगान लिया जाता है । अब भी इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि पूरा लगान नहीं माफ किया जाय तो कम से कम आधा तो कर ही दिया जाय ।

जंगल की बहुतायत के कारण केटल ब्रीडिंग का उद्योग-धन्धा अच्छी तरह चल सकता है जिसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया ।

मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि कई आवश्यक बातों का करौली में कोई स्थान ही नहीं रखा है । वहां कालीसिल का बांध जिसका विवरण कल एक मेरे माननीय साथी महोदय ने किया है उसके लिए सरकार ने इस सम्बन्ध में बजट में कोई रुपया नहीं रखा है । उसके अलावा मामचारी बांध जो कि एक बहुत छोटा बांध है और जिससे मैं अनुभव करता हूं कि ५०० बीघे से ज्यादा पिलाई नहीं हो सकती है और उसमें २ लाख १३ हजार की स्वीकृति बजट में उसके लिए रखी है जबकि कालीसिन्ध बन्ध से, मैं अनुमान करता हूं कि ३ हजार

बीघे की पिलाई हो सकती है । तो उसके लिए बजट में क्यों नहीं रुपया रख गया है जब कि एक छोटे से बन्ध के लिये रुपया रख दिया गया है ।

इन सारी बातों को देखते हुए मुझे दुख के साथ सदन से यह निवेदन करना पड़ता है कि इस बजट में करौली की उन्नति के लिये कुछ न कुछ अवश्य ध्यान रखना चाहिए ।

श्री रघुराजसिंह:--श्री अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर काफी वादविवाद हो चुका है और कई सज्जन अपनी अपनी राय बजट पर पेश कर चुके हैं, लेकिन मुझे खेद है कि जो बजट पेश किया गया है वह करीब ९३।। लाख रुपये घाटे का बतलाया गया है । अच्छी सरकार का यह उद्देश्य नहीं होता है कि वह अपने बजट को घाटे में चलाये । रियासतों को विलीन करके राजस्थान कायम किया गया है, उस वक्त में करीब करीब सभी रियासतों की ऐसी हालत थी कि जिसमें किसी प्रकार का घाटा नहीं था, बल्कि खास खास बड़ी २ रियासतों ने तो काफी रुपया राजस्थान को दिया था । उसमें से बीकानेर और जयपुर ने करीब करीब ५,५ करोड़ के और दूसरी रियासतों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन कोटा राज्य से भी २ करोड़ रुपये की रकम राजस्थान को दी गई थी । उस पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला था । मैं बता देना चाहता हूं कि फिर समझ में नहीं आता कि क्यों इस तरह से घाटे का बजट बनाया गया है । वैसे तो हर जगह से जिस तरह चाहे उस तरह खर्च किया जा सकता है, लेकिन अच्छी गवर्नमेन्ट के लिए यह उचित है कि जितनी गुंजाइश हो उसी के मुताबिक खर्च किया जाना चाहिये और कुछ बचाये जाने की भी आवश्यकता है और उसे रखकर एक अच्छा बजट बनाना चाहिये जिससे कि घाटे का मौका नहीं आए । आवश्यकता पड़ने पर, जरूरी काम होने पर ऋण लेना या कर लगाना उचित है लेकिन साधारण हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए । राजस्थान बनने के बाद में कई अधिक कर लगाये जा चुके हैं और अब उचित नहीं है । एग्रिकल्चर, इनकम टेक्स आदि दूसरी तरह के टेक्स वसूल किये जायं । काश्तकारान पर और बोझ लाद दिया जाय और गवर्नमेन्ट या अन्य कोई कर्मचारी जिनका इससे सम्बन्ध है वह अपना एशोआराम करें !

जैसा कि हमारे माननीय नेता ने जाहिर किया था कि बजट में जो मदें हैं उनमें से मिसाल के तौर पर २,४ के बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं । फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट (वन विभाग) में ४५,७०,००० रु० की आमदनी बजट में है और २७ लाख से ऊपर का खर्चा बजट में बताया गया है, लेकिन हिसाब से आमदनी का १/३ याने १५ लाख रुपये से ज्यादा खर्चे की मद में नहीं होने चाहिए । मन्त्री लोगों को कार एलाउन्स नियत करके करीब लाख सवा लाख की भी उसमें बचत की जा सकती है । (करतल ध्वनि विपक्ष की ओर से) ।

वायुयान विभाग जो है वह फिजूल मालूम होता है । उसकी कोई खास जरूरत नहीं है; जैसा कि कहा गया है । मन्त्री मण्डल को जरूरी काम के लिए

वायुयान की आवश्यकता पड़ती हैं । इस तरह से १,१०,५०० रु० जो इसके लिए बजट में हैं उनकी बचत हो सकती है ।

पॉवर हाउसों में जो घाटा दिखाया गया है, १४॥ लाख के करीब का, तो इसके चलाने से गवर्नमेन्ट को क्या फायदा है, इसको लीज पर देकर १४॥ लाख रुपये की बचत की जा सकती है ।

मेडिकल डिपार्टमेंट में पहले जो पी० एम० ओ० या सी० एम० ओ० हुआ करते थे वही डाइरेक्टर आफ मेडिकल सर्विसेज का भी काम किया करते थे, लेकिन अब डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर और असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ मेडिकल सर्विसेज मुकर्रर कर दिये गये हैं । पी० एम० ओ० या सी० एम० ओ० अलग कर दिये गये हैं; इसलिए यह इतने फालतू आदमी होने से बहुत खर्चा हो गया है । यह जगह तोड़ दी जाय और दोनों का काम शामिल कर दिया जाय तो यह भी बचत हो सकती है।

इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्रेटरियेट में भी काफी स्टाफ कम हो सकता है । उस पर ध्यान दिया जाय तो लाखों की तादाद में उससे कमी की जा सकती है।

अकसर यह भी देखने में आया है कि राजस्थान के बहुत से कर्मचारी सरप्लस में डाल दिये जाते हैं और उनको तनख्वाह तो दे दी जाती है लेकिन काम कुछ भी नहीं लिया जाता है । तो क्यों नहीं उनको नियमों के अनुसार रिट्रेन्च (कम) करके फालतू आदमियों को नहीं रखा जाय । इससे बहुत कुछ बचत हो सकती है ।

एग्रिकल्चर डिपार्टमन्ट में १७,९१,००० रु० से ऊपर खर्चा बतलाया गया है और आमदनी २,२५,००० रु० की है । इसकी वजह समझ में नहीं आती है। अगर यह ठीक नहीं चलता है तो इसको तोड़ देना चाहिए या कुछ सुधार अवश्य होने चाहिए ।

स्टेट गेरेजज् में ३॥ लाख के खर्चे का बजट रखा गया है । हर एक डिपार्टमेन्ट में जो इस वक्त सरकार की तरफ से मोटरें हैं, बहुत से ट्रक बेकार पड़े हुए हैं । देखने में आता है कि उनका दुरुपयोग किया जाता है । सरकारी काम में मोटरें कम आती हैं और प्राइवेट काम में, निजी काम के लिए, विशेष काम में ली जाती हैं । अगर इसको बचायें तो वही मोटरें हर डिस्ट्रिक्ट या डिविजन में सेन्ट्रल गेरेज नियत हो जावे । जो जरूरत होने पर दूसरे विभागों को वहां से मोटरें दे दी जांय । इसमें भी १॥, २ लाख की बचत हो सकती है ।

सिविल सप्लाइज डिपार्टमेन्ट से सिवाय जनता को तकलीफ और अत्याचार के कोई फायदा नहीं हुआ है । इसलिये यह महकमा तोड़ दिया जाय तो १८ लाख की बचत हो सकती है । इस तरह से मेरे पहले बोलने वाले सदस्यों ने काफी आंकड़े बतलाये हैं जिसके विषय में मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता।

इससे काफी बचत हो सकती है जिससे टेक्स के बोझ को कम किया जा सकता है और सरकार सुचारु रूप से चलायी जा सकती है। बजट के देखने से यह मालूम होता है कि कोटा डिविजन के ऊपर करीब बजट के अन्दर ४॥ लाख रुपया केपिटल वर्कस पर खर्च किया जा रहा है। बजट को देखने से ये ज्ञात होता है कि कोटा डिविजन के ऊपर सरकार का किसी तरह से भी ध्यान नहीं। यह नेगलेक्टेड एरिया सा मालूम पड़ता है। जिसके ऊपर न तो मन्त्री महोदय का ध्यान है और न कोई अफसर का जो वक्त पर उसकी देखभाल करता हो। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहां तक कि ऊपर से देखभाल न होने से मुकामी अफसर भी लोगों की कठिनाई का ध्यान नहीं रखते; कोई सुझाव पेश नहीं करते। कोटा राजस्थान में सम्मिलित है। उसके लिए ७८ लाख रुपये से ऊपर बिल्डिंग और रोड्स के नाम से सन् १९५१-५२ में दर्ज किये गये है मैं, माननीय सम्बन्धित मन्त्री से इस विषय में जानकारी चाहता हूं, कि ? अध्यक्ष महोदय की इजाजत से, कि जिसमें कितनी रकम कोटा डिविजन के ऊपर खर्च की गई है ? यह बात जो की गई है, उसमें से कितनी सड़कें बनाई गई है, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई, कितनों की नहीं की गई। आज कोटा डिविजन की सड़कों का यह हाल है कि उसकी दशा राजस्थान की सभी सड़कों से बहुत खराब हो रही है, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं। सड़को के जरिये हमारे मन्त्री गण आये तो उनको पता हो सकता है सड़कों की स्थिति क्या है। वायुयान द्वारा मन्त्री महोदय सफर करते हैं, उनको सड़कों की जांच कैसे हो सकती है। उनको पता नहीं चलता कि सड़कें किस प्रकार खराब पड़ी है। थोड़ी सी देर के लिए भी वे वहां नहीं जाते, सड़कों की खबर नहीं लेते। कोटा राज्य जब रियासत थी उस समय सड़कों का जो हाल था वह आप से छुपा नहीं है। अब राजस्थान में मिले तीन वर्ष हो गये, मेरे ख्याल से कोटा डिविजन में गत वर्षों में किसी भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई। वहां सड़कों का नया निर्माण किया जाता है लेकिन पुरानी सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नयी नयी तजबीजें पेश की जाती हैं। इस सम्बन्ध में मेरी तजवीज है कि नयी की अपेक्षा पुरानी जो सड़कें हैं उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मसलन कोटा डिविजन में इस साल कुछ लाख की रकम सड़कों पर खर्च करने के लिए बजट में दर्ज की गई है उसके लिए मेरा निवेदन ह कि जो आवश्यक काम हो वह जरूर किये जांय। कोटा राज्य म किशनगंज हैडक्वार्टर थाना मेन रोड जाती है, एक अजमेर जयपुर की ओर और दूसरी झालावाड़ होती हुई बम्बई की तरफ और तीसरी शिवपुरी की तरफ। शिवपुरी की तरफ जाने वाली सड़क ५० मील सड़क कोटा राज्य ने गवर्नमेन्ट से कुछ इमदाद लेकर उसको पक्का बनाया था। उसमें से १५ मील का टुकड़ा बाकी रह गया था लेकिन कई वर्ष हो गये आजतक १५ मील का वह टुकड़ा नहीं बन पाया है। मैन रोड खाली पड़ी है। उसका होना परमावश्यक है; बनिस्पत इसके कि दूसरी सड़को का निर्माण किया जाय, जिसको साल दो साल के लिए स्थगित किया जा सकता है। ?

दूसरी सड़कों की मरम्मत के विषय में भी मैं तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। बांरां कोटा डिविजन की सब से बड़ी मंडी है। इस सड़क से सब से अधिक

अनाज गाड़ियों द्वारा वहां पर मंड़ी में आता है। इस सड़क को बने करीब १२, १४ साल हो गये। उसके बाद उस पर एक कंकर भी नहीं डाला गया। उसका नतीजा यह हुआ की जगह जगह उसमें गड्ढे नजर आरहे हैं और जनता को बड़ी कठिनाई और तकलीफ होती है। इस तरह से किशनगंज तहसील है उसकी भी यही हालत हैं कि वहां जो पुलिया आदि है उनकी मरम्मत नहीं होने से वे गिर रहे हैं। इस प्रकार के छोटे छोंटे काम हैं; यदि वक्त पर उनकी जगह रिप्लेस कर दिये जाते हैं तो उनको बनाने में कठिनाई नहीं होती है और उतना पैसा भी खर्च नहीं होता है। हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट का यह हाल है कि जो कन्ट्राक्टर्स बेचारे काम का ठेका लेते ह उनका पेमेंट न होने से उनकी शिकायत यह रहती है। अभी तक हमारा पुराना पेमेन्ट ही नहीं हुआ; नये काम में हम कैसे हाथ डालें। अफसरों को जिसमें कुछ मिलता है उनका काम पूरा कर दिया जाता है। बेचारे छोटे छोंटे ठेकेदारों का हाल बहुत बुरा है। छोटे छोटे ठेकेदारों के कागजात वर्षों तक पास नहीं ते। बांरा मागरोल रोड़ पर खेडली के स्थान पर जो पुल बनाया गया है उसके ठेकेदार की अबतक सुनवाई नहीं हुई है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सम्बन्धित मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस बारे में चीफ इन्जीनियर साहब को हिदायत करें कि जल्दी से जल्दी जांच करके उसे रुपये दिलानें की कोशिश करें।

कोटा डिवीजन को नेग्लेक्टेड करने का एक कारण यह भी है कि जो सरकार बनी है उसमें वहां का कोई प्रतिनिधि नहीं है जो इस डिविजन के दुःख सुख को उनके सामने रख सके और बतला सके। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अब जहां तक मुझे मालूम है मिनिस्ट्री में दो स्थान खाली हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसमें एक पर कोटा के किसी व्यक्ति को स्थान दिया जाय तो बहुत उचित होगा।

मैं माननीय सिविल सप्लाई मंत्री महोदय से यह दर्याफ्त करना चाहता हूं कि तहसील किशनगंज शाहाबाद जो कोटा डिस्ट्रिक्ट में है उसमें लेवी किस आधार पर ली गई; जब कि कुछ। जगह नहीं ली गई। इस विषय में कोई हुक्म नहीं हुआ। यह मुकामी अफसर की धान्धली और मनमानी है और यह एक मुकामी अफसर की धांधली और मनमानी से वसूल हो रही है। किसानों के पास धान देने को नहीं ह; मगर फिर भी सरकार उनको तंग करती है। किसान बाजार से धान मोल लेकर सरकार को दे रहे है। मैं इसका जवाब मिलने की मंत्री महोदय से आशा रखता हूं। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि तम्बाकू पर ६० रुपये फी बीघा का कर लिया गया है। वह किस हुक्म के तहत में लिया जाता है। जब लोग बाग पहले ही करों के बोझ से तंग आ रहे हैं, जिसमें खास कर गरीब किसान, तो यह कर क्यों लगाया जारहा है, इसके मुतल्लिक भी माल मंत्री जवाब देने की कृपा करेंगे। तीसरी बात, शिक्षा मंत्री से मेरा यह प्रश्न है कि प्राइमरी स्कूलों को खोलने के जो असूल थे उन्ही असूलों के अनुसार कोटा शहर में प्राइमरी स्कलें बनी। राजस्थान सरकार ने भी उन सिद्धान्तों को मानते हुए भी कोटा शहर में प्राइमरी स्कूलें जारी रखी थी। उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किये जाने के बजाय बन्द कर दी गई है। इसका कृपा करके जवाब देने की कृपा करें।

(माननीय अध्यक्ष ने श्री रघुराजसिंह को समय की समाप्ति की सूचना दी। उस पर रघुराजसिंह ने अपना भाषण जारी रखने के लिये दो मिनट की अवधी और मांगी ।)

श्री रघुराजसिंहः-- अब एक प्रश्न मेरा है वह यह है कि दो लाख रुपया कोटा से सरकार को मिले; वे रुपये किस काम में खर्च किये गये हैं और उससे कोटा की पब्लिक को क्या लाभ हुआ है ? इसका जवाब भी सदन की जानकारी के लिये मुझे मिलना चाहिये ।

माननीय अध्यक्षः- Question Hour नहीं है।

१९५१-५२ में ४६ लाख ३० हजार और ११ लाख ४० हजार जो बजट में मुकर्रर हैं उनमें कोटा डिविजन के मुतल्लिक कोई प्रोविजन रखा गया है या नहीं और नहीं रखा गया है तो इसकी क्या वजह है ? क्या कोटा में कोई इस तरह का काम नहीं है जिसे किया जावे । मैं यह अर्ज करूंगा कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये । चूंकि समय नहीं रहा है इसलिये इस समय में अब अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

एक माननीय सदस्यः--ओन दी पाइन्ट ओफ ओर्डर सर, दोनों पक्षों के लिये टाइम नियुक्त किया गया है क्या इसके लिये कोई हिसाब रखा जावेगा ।

माननीय अध्यक्षः- अवश्य रखा जावेगा ।

श्री मोतीचन्दः-- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क पहले बजट पर मैं अपने विचार प्रकट करूं इससे पूर्व हमारे माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस पर कुछ प्रकाश डालूं राजस्थान में विलय होने से पूर्व अनेक रियासतें थी और उनसे प्राप्त राशि १९ करोड़ रुपये की ठहराते हैं । १७ करोड की सिक्योरिटी और दो करोड ग्यारह लाख के शेयर्स । इस प्रकार १९ करोड़ कुछ लाख रुपयों की राशि १-४-५२ को थी । उसके बाद ४ करोड़ १५ लाख की कमी होकर अब १५ करोड और कई लाख की रह जाती है । अभी जो बजट पेश किया गया है उसमें ऐसी अनेक मदें दिखाई गई हैं उन्हें और जो बजट में घाटा दिखाया गया है उसको देखने से मालूम होता है कि जो घाटा दिखाया गया है वह संपूर्ण घाटा नहीं है सम्पूर्ण मात्रा में जो यह घाटा बहुत होना चाहिये था छिपा दिया गया हैं शेयर्स की जो लागत है वह वर्तमान दरों के हिसाब से बहुत कमती की हो जाती ह और सरकार का जो रुपया अनाज के अन्दर लगा हुआ है वह भी कई करोड रुपया है । इसमें भी वर्तमान समय के भावों को देखते हुए काफी घाटा होना चाहिये । इस प्रकार जो घाटा दिखाया गया है उससे भी डेढ दो करोड़ का घाटा और बढ़ जाता ह । इस प्रकार सरकार की मूल पूंजी में ७ करोड़ रुपयों की और कमी हो जावेगी ।

मैं, इस सारी स्थिति को दृष्टिगोचर रखते हुए सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को ठीक बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची और इस समय बढते हुए भ्रष्टाचार को रोका जावे । यदि यही हालत हमारी आर्थिक असूलों की रही तो इसमें कोई संदेह नहीं कि एक रोज हमारी सरकार बुरी तरह से फैल होगी क्योंकि इस प्रकार से आय का हिसाब किसी भी सरकार को बनाये रखने में सहायता नहीं दे सकेगा । इतनी जल्दी पूंजी का ह्रास होने का मूल कारण भूतकाल की अनेक अयोग्य सरकारों पर है (हिअर हिअर) उनकी यह जिम्मेवारी थी कि वे जो अनेक रियासतों से रुपया मिला है उसको संभाल कर रखते और उसका दुरुपयोग नहीं करते । मगर आपने उनको काफी संख्या में शेअर्स और सिक्योरीटीज में खर्च कर डाला । इस प्रकार हमारी पूंजी जो है वह दिनों दिन नष्ट हो रही है और उसको बचाने का कोई उपाय अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है । जो डिवीजन हैं, पुरानी स्टेटे हैं, उनके द्वारा जो राशियें आई थीं उनको अन्य उद्योग धन्धों में दे दी । लेकिन तीन साल होने को आये हैं इस राशि के जो उनके लिये रखी है एक पैसा भी खर्च नहीं किया; जब कि एक अलग फंड के रूप में अलग रखी है । इसी प्रकार बीकानेर से कुछ राशियें आई मगर वो राशियें उस पर खर्च नहीं की गई, जिसके लिये वे रखी गई थीं Free Supply of Water and Public Welfare Fund. से १४ लाख रुपये आये । उसी प्रकार डेवलपमेन्ट फन्ड के लिये बीकानेर से ३१ लाख रुपये आये; लेकिन इस वक्त जो स्थिति वहां के डेवलपमेन्ट की है; जो हालत वहां की सड़कों की हो रही है उसको देखते हुए कोई भी समझदार व्यक्ति उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । जब इसके लिये रुपया अलग रखा हुआ था तो क्या कारण है कि उस रुपये को उसी के लिये काम में नहीं लिया गया । क्यों नहीं उस राशि का उसके विकास के लिये उपयोग किया जावे ? मैं आशा करता हूं कि उस राशि को जल्दी से जल्दी सड़कों की हालत को जो बिगड़ रही है ज्यादा बिगड़ने से रोकने के लिये, जो वहां की सड़कों की जो दुर्दशा हो रही है उस पर व्यय किया जावेगा ।

अब इन सब बातों के अलावा हमें जो बड़ी बात सरकार की तरफ से शिक्षा पर २॥ करोड़ रुपयों की जो राशि दिखाया गया है वह स्तुत्य है लेकिन उसका पूर्ण रूप से उपयोग कहां तक होगा; यह नहीं कहा जा सकता ।

पिछले साल जब पाठ्य पुस्तकों को स्कूलों में लागू किया तो उन्हें न जाने किस ढंग से, किस समझदारी से लगाया गया । उनमें जो बातें लिखी गई है वे इतनी गलत और बेजा हैं कि उनके बारे में कुछ न कहना ही अच्छा है । जो बड़े-बड़े लेखक आज जिन्दा हैं उन्हें उन पुस्तकों में मरा हुआ बताया गया है और जो मर गये हैं उन्हें जिन्दा बताया गया है । ऐसी हालत में हमारे यहां के विद्यार्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है । यह है हमारी सरकार द्वारा खर्च किये जाने वाले पैसे का नमूना; जो न्यायपूर्ण ढंग से व उचित रूप से हो रहा है । मुझे आशा है कि अब जो कुछ होगा वह ठीक ढंग से ही होगा ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार की जो व्यवसायिक

व औद्योगिक नीति है वह भी ठीक ढंग से नहीं चलाई जाती। यदि सरकार को यह नीति ठीक ढंग की होती तो इससे सरकार को कुछ मदद, घाटा मिटाने में मिल सकती थी। बीकानेर डिविजन में कई ऐसी माइन्स और मिनरल्स हैं जिनके विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। ये पिछले ३ वर्षों में यदि ठीक ढंग से उपयोग में लाई जाती तो उनसे लाखों रुपयों की वार्षिक आय सरकार को होती। बजट में कोई नई चीज नहीं है। उसी पुराने ढर्रे पर चला आ रहा है और वैसा का वैसा रखा गया है। लेकिन मैं आशा करूंगा कि अब जो कुछ भी किया गया है और जो रकम मंजूर की जायगी उसे ठीक ढंग से खर्च किया जायगा और हमारी निर्माण की योजनाओं में जो आम जनता के हित की बातें हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान रख कर इस बजट की रकम को उचित रूप से व्यय किया जायगा और जिस प्रकार पी० डब्लू० डी० आदि में सड़कों व इमारतों पर जो रुपया लगाया जाता है उसमें से आधा न मालूम कहां गायब हो जाता है क्योंकि हमारे बजट में जो रकम दिखाई जाती है वास्तव में उन चीजों पर इतना रुपया नहीं लगता बल्कि आधे से भी कम लगता है। मैं आशा करूंगा कि सरकार इस कार्य में जरूर सफलता प्राप्त करेगी। इतना कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री इब्राहिमः—सदन महोदय, आजाद राजस्थान की एसेम्बली में यह पहला बजट पेश हुआ है। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो राजस्थान छोटी-मोटी १८—२० रियासतों से बना है, उन सब रियासतों में अपना-अपना अलग बजट चलता था और उनके भी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रटरी, हाई कोर्ट वगरह हरएक चीज होती थी और उसके साथ उनके अलग महल—महलात, शिकारखाने, महमानघर वगैरा होते थे; परन्तु उनको किसी की इमदाद नहीं लेनी पड़ती थी। वे अपना काम खींच तान करके आप ही चलाते थे। हमारे यहां पहला बजट घाटे का पेश हुआ है। यह अफसोश की बात है। इसमें जो चीजें रखी गई हैं उनमें सड़कों, कस्टम जैसे बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। कस्टम आदि के मुत्तालिक खास तौर से अर्ज करूंगा। राजस्थान में ९० प्रतिशत आबादी खेतीबाड़ी वालों की हैं। दूसरी हर चीजों की ओर ध्यान दिया जाता है। सदस्यों में से भी ज्यादातर लोग गांवों से आये हैं। गांवों की तरक्की का ध्यान न पहले दिया जाता था और न अब दिया जाता है। शहरों मे हर तरह की सहूलियतें हैं, मसलन सड़कें हैं, बिजली हैं, नल हैं और नये तालाब बन जावेंगे। दूसरीं आराम की चीजें भी मिल जावेंगी; लेकिन गांव वालों के लिये कोई चीज न पहले थी और न आज है; बल्कि आज ज्यादा अंधेर नजर आता है क्योंकि पहले खेती बाड़ी से काम चलाने वाले लोगों के लिये खास रियायतें रखी जाती थी; पर आज गांवों में रहने वाले कब्र में रहने वाले की तरह हैं। उनके लिये कोई सुख सुविधायें नहीं है। न उनके लिये तालीम का माकूल इन्तजाम है, न दवाई का। जब गांव वाले सुनते हैं कि उनमें से फलां आदमी का बच्चा युनिवर्सिटी में पहुंच कर तालीम ले रहा है और आगे चलकर तरक्की करेगा तो गांव वालों के दिलों में उमंग पैदा होती है और वे तालीम की तरफ ध्यान देने लगते हैं। लेकिन आज के बजट में यह चीज नहीं नजर आती। पिछड़ी हुई जातियों पर जितना खर्च किया जाय, कम है। जो पिछड़े

हुए हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च होना चाहिये। साथ में अर्ज करूंगा कि उनकी तरफ ध्यान न देना, इन्साफ नहीं है। गांवों में जो लोग रहते हैं वे ही हम सब की असली ताकत है और उन्हें छोड़ देंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। असली चीज खेती है। वह किसान कड़कड़ाती धूप में, सर्दी में व बरसात में भारी मेहनत करके आपके लिये अनाज पैदा करता है, हल चलाता है, उसकी तरक्की की तरफ अपना ख्याल जाना बहुत जरूरी है। दूसरे कामों के लिये जहां लाखों रुपयों की स्कीमें चल रही हैं आज कल दूसरे स्थानों में हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वालों के लिये जिस तरह के काम हो रहे हैं उसी तरह आपके यहां भी होना चाहिये। आपकी स्कीमें कागजों में चलती हैं; उन्हें नीचे उतर कर गांवों के लोगों को जगाने के लिये काम करना चाहिये। जिस तरह का काम आजकल यू० पी० और पंजाब आदि में हो रहा है उसी तरह आप को भी करना चाहिये। शेख अब्दुला के काश्मीर को जाकर देखिये; उस नये काश्मीर में जहां पहले तालीम नहीं थी और गरीब किसानों की हालत खराब थी आज उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज उनकी बुलन्द आवाज कितनी ऊंची है। आप वहां जाकर देखिये उसने जो तरीका अख्तियार किया है उसे देखिये। आप भी इंसान हैं। लेजिस्लेटिव एसेम्बली इन चीजों की तरफ ध्यान देगी तो सब की तरक्की होगी। गांव में रहने वाले मंडी में आकर गेहूं बेचते हैं तो हमारी सरकार १६ रुपये मन खरीदती है इसमें २॥) रुपये मन ले लेती हैं। सरसों पर २५ रुपये मन के लग जाते हैं। इसका मुकाबला आप पंजाब और यू० पी० से करिये। वे आजादी के साथ सरसों बेचते हैं गांवों में रहने वाले किसानों की दिक्कत की तरफ ध्यान देना चाहिये। आज सरसों का भाव गिर गया है; वे सरसों बेचते हैं। इसी तरह बछड़ों पर २५ रु०, १५ रु० कस्टम देनी पड़ जाता है। गावों की तरक्की की ओर आप के बजट में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये था।

इसी तरह जंगल में बहुत कुछ सुधार कर रहे हैं और होना चाहिये; लेकिन साथ ही साथ यह ध्यान देना चाहिये कि जंगलों में ऐसे ऐसे जानवर पैदा हो रहे हैं जो खेतीबाड़ी को उजाड़ रहे हैं। खेतीबाड़ी का लाइसेंस बड़ी मुश्किल से किया जाता है जब अनाज की कमी है तो लाइसेन्स आसानी से क्यों नहीं दिया जाता ?

रात रात भर सर्दी की मौसम में किसान कड़ाके की ठंड में रखवाली करता रहता है मगर उसको उसका पूरा फल नहीं मिलता है। यह चीज जैसा कि यू० पी० में और पंजाब में होता है कि वहां किसी बन्दर को मार कर उसकी पूंछ लाकर देने वाले को ५) रु० इनाम दिया जाता है, इसी तरह लुटेरों डाकूओं को पकड़ने वाले को भी इनाम दिया जाता है। जो डाकुओं को पकड़ता है, अपनी जान को जोखम में डालता है तो उस थानेदार को, उस अफसर को इनाम मिलना ही चाहिए, मगर यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

काश्तकारों के मुतल्लिक भी मुझे यह कहना है कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देना लाजमी है। जो हकीकत किसान की है वह बड़ी नाजुक है। जो जमीन

पर खेती करता है, अनाज पैदा करता है उनको जमीन मिलनी ही चाहिए । इसकी ओर ध्यान देना चाहिए । जमीनों के लिए हमारे अनेकों किसान मारे मारे फिर रहे हैं लेकिन उन्हें जमीनें नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों की तादाद ४०–५० हजार के करीबन है । महात्मा गांधी के शब्दों में इसे रीढ़ की हड्डी कहा गया है । गुड़गांवा, नौ गांव आदि में जब इसकी गड़बड़ हुई थी तो उन्होंने अपने शिष्य श्री सुन्दरलाल, श्री बिनोबाभावे, श्री गोपाला स्वामी आयंगर, इन सबको, वहां भिजवाया था । इसी तरह से मुसलमानों की हालत हो रही है । उनमें से कइयों की हालत यह है कि वह अपने मकान के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं । अपने कुएं हैं जिसमें हजारों पानी भरते हैं, पर हम पानी नहीं पी सकते । अपने खेत हैं, अपने बाग हैं दरख्त हैं, लेकिन हम कदम नहीं रख सकते । इस तरह हमारा मजाक नहीं होना चाहिए, मेवों की इस तरह की हालत को सुधारने के लिए हकूमत को मदद करनी चाहिए ।

इसी तरह से पुलिस का महकमा है । उस पर हजारों रुपया खर्च किया जा रहा है और अब भी उस पर खर्च बढ़ाया जा रहा है; मगर वास्तव में देखा जाय तो वह फिजूल है, पब्लिक सबसे अधिक इसी महकमे से तंग आ चुकी है । इस पर लाखों रुपया खर्च होता है पर इसीसे पब्लिक को अधिक परेशानी उठानी पड़ती है । पुलिस में जब आदमी पहुंच जाता है तो उसका फर्ज बन जाता है कि वह पब्लिक के जान माल की हिफाजत करे । मगर ऐसा होने के बजाय वह खुद ही लुटेरों में मिल जाते हैं । अच्छे बड़े २ डाके पड़ते हैं और उनका पता लगने के बावजूद भी उन्हें छोड़ दिया जाता है । हम भरतपुर में रहते हैं, हम देखते हैं कि वहां एक घाटोल गांव है, वहां अच्छा बड़ा से बड़ा डाका पड़ा और असली मुजरिम गिरफ्तार भी हो गया मगर उसे छोड़ दिया गया और उसकी जगह किसी फर्जी मुजरिम को पकड़ा जाता है और फिर रिहा कर दिया जाता है । तो इस तरह से, इस महकमे से जो पब्लिक को फायदा होना चाहिए, उसकी जगह तो उसे बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है, इस वजह से यह खर्चा फिजूल है । इसका रुपया हकूमत अगर किसानों के फायदे के लिए खर्च करे तो वह अपने जान माल की हिफाजत भी कर सकता है और उससे अपना मुनाफा भी कमा सकता है ।

रिश्वतखोरी का बाजार भी इतना गरम हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है । काश्तकारों को जमीनें भी रिश्वतें ले लेकर दी जाती है तो आपको इस ओर भी पूरा ध्यान देना है । चोरबाजारी और रिश्वतखोरी को अपने मुल्क से निकालकर बाहर करना है । क्या कारण है कि चीन जब दो साल में अपनी मुश्किलातों को दूर कर सकता है, शेख अब्दुल्ला जब इतनी बड़ी मुसीबतों के बीच भी इन्तजाम कर सकता है, वहां पर पाकिस्तान के झगड़े और कई बड़ी २ दिक्कतों के होते हुए काश्मीर में रिश्वत एक इंच की भी नहीं पायेंगे तो फिर क्या वजह है कि आपके सूबे में ही ऐसा होता है । आपको यह सब देखना चाहिए । ५–५, १०–१० आदमियों की कमेटियें बैठा कर हर महकमे को मुलाहिजा करना चाहिए, कोई कमेटी थाने को देखे, तो कोई कमिश्नर ऑफिस को देखे तो कोई जेल को देखे, इस तरह से सब जगह की मलाहिजा करते रहें । जिस

तरह कि पंजाब में होता है कि एक कमिश्नर जा जा कर कभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को देखता है, कभी जेल देखता है, कभी थाने को देखता है तो वहां गड़बड़ होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता है ।

(माननीय अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री मोहम्मदइब्राहिम:—मैं एक दो मिनिट और बोलूंगा ।

मुझे कई बातें कहनी थीं । मगर साहिबेसदर ने हुक्म दे दिया है । मैं एक खास बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी तक भरतपुर के अन्दर मेवों पर मुकद्दमे चल रहे हैं, सभी जगह के मुकद्दमे उठा लिए हैं तो फिर क्या कारण है कि वहां पर ही मुसलमानों पर मुकद्दमे चलते रहें । मैं हकूमत से दर्ख्वास्त करूंगा कि वह इस ओर तुरन्त ध्यान दे और इन मुकद्दमों को तुरन्त उठा ले । इसी तरह से वहां की मस्जिदों के अन्दर अभी भी मुसलमान भरे पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालें ।

हमारा इलाका बॉर्डर का इलाका है; उससे यू० पी० और पंजाब का इलाका लगता है । उन इलाकों के अन्दर सब जगह सड़कें हैं मगर हमारे वहां नहीं है, इस लिए हमें उन लोगों के सामने शर्मिन्दा होना पड़ता है कि हमारे यहां पर सड़कें तक भी नहीं हैं । इन सब बातों की ओर आपको तवज्जुह देनी है, इन सब चीजों का आपको इंतजाम करना है; तभी आपकी हकूमत ठीक तरह से चल सकती है । बस मैं तो इतना कह कर अपना स्थान लेता हूं ।

श्री गंगासिंह:—माननीय वित्त मंत्रीजी के शब्द बजट के संबंध में जो कहे गये हैं कि "हमारी यह संपूर्ण कहानी मुश्किलों और कठिनाइयों से भरी हुई है" और उन्होंने जो इस कहानी के लिए दु:ख प्रकट किया है उसके लिए मैं भी उनके साथ में अपना दु:ख प्रकट करता हूं । परन्तु श्रीमान् मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि इस दु:ख भरी कहानी का क्या कारण था ? किसके जरिये यह दु:ख भरी कहानी हमारे सामने पेश हुई है और क्या यह कहानी सुखमयी व शान्तिमयी नहीं बनाई जा सकती थी ? श्रीमान, यह कहानी हमारी ऐसी कहानी नहीं थी जो कि सुखमयी व शान्तिमयी नहीं बन सकती थी, परन्तु जिनके ऊपर इस कहानी का बोझ डाला गया था वे ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने कि इस ओर ईमानदारी व कष्ट के साथ कुछ भी ध्यान नहीं दिया । जिसका कि परिणाम यह हुआ कि यह कहानी आज हमारे सामने दु:ख का रूप लिए प्रस्तुत हुई है । इन कठिनाईयों व मुसीबतों की कहानी के कई कारण हैं जिसके कारण यह दु:ख भरी प्रतीत होती है । उन सब कारणों को मैं आपके सामने समय की कमी के कारण रख नहीं सकता । केवल २,३ कारणों को लेकर ही चलूंगा और आपको उस स्थिति में उपस्थित कर दूंगा । आप उन कारणों को देखेंगे तो आपके सामने एक नक्शा आ जायगा जिसके कारण आप खुद यह निश्चित कर सकेंगे कि इसके कारण क्या क्या थे और किस तरह यह कहानी बनी ?

सर्व प्रथम जो इस दु:ख की कहानी के कारणों में से एक कारण जनरल

एडमिनिस्ट्रेशन को लेता हूं। हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में भी सब कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ एक ही बात को लेकर में चलता हूं, वह है सरविसेज क्लास। सरविसेज क्लास (Services class) पर जो आघात हमारी पिछले दिनों की गवर्नमेन्ट द्वारा किया गया है वह सोचनीय है। इसके जरिये बहुत आपत्तिजनक कार्य हुए हैं जिसके कारण यदि बजट में आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कई ऐसी ऐसी नियुक्तियां की गई हैं जिसके कारण काफी सरकार का नुकसान हुआ और ऐसी नई नई पोस्टें (Posts) भी क्रियेट (Create) की गई जिसके कारण सरकार को बहुत अधिक पैसा खर्च करना पडा। में केवल जैसा कि सरकारी पक्ष के एक व्यक्ति ने कहा है "आप एक्जाम्पल्स (उदाहरण) देकर किसी को यहां पर रखें"। एक दो एक्जाम्पल्स (उदाहरण) आपके सामने रखूंगा, जिसके जरिये आप यह जान सकेंगे कि कैसे २ और किस तरह से सरविसेज क्लास पर कुठोराघात किया गया था। सरविसेज क्लास की ऐसी एक्जाम्पल्स जिसके द्वारा सरविसेज क्लास पर जो कुठाराघात किया गया है वह सैंकडों हैं। इसकी एक पुस्तक भी लिखी जा सकती है। परन्तु में कुछेक लेकर आपके सामने आऊंगा।

एक महाशय जो कि गन्तव्य मंत्री के भानजे थे जो कि २ साल से नौकरी से बाहर रह रहे थे; चूंकि वे प्रधान मंत्री जी के रिश्तेदार थे इसलिऐ झट उन्हेंनौकरी से बाहर रहते हुए भी वापिस मंत्री जी द्वारा नौकरी में ले लिए गये और शासन में एक अच्छे ओहदे पर ले लिये गये। अब में जब कि एक तरफ श्री वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि हमारे फाइनेंस में बहुत कमी है, बजट घाटे में दौड़ रहा है और दूसरी और जो कि सरकार के बाहर निकाल दिये गये थे और जो २,२ साल बाहर सरकार की नौकरी में न थे, उनको भी वापिस लेकर उनको नौकरी न करने के समय की भी तनख्वाह मुफ्त में दी जाती; है यह, कैसा न्याय है?

इसके अलावा, श्रीमान् में एक और उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। एक महाशय जो कि गन्तव्य प्रधान मंत्री के पी.ए. रह चुके थे, और वे भी प्रधान मंत्रीजी के ऊपर जो केसेज चलाये गये थे उनमें शामिल थे. केसेज के चलने के दौरान में उनको सस्पेन्ड किया गया था, और जब वे प्रधान मंत्री राजस्थान सरकार के प्रधान मंत्री बन जाते हैं तो नक्शा और भी बदल जाता है। जो पी० ए० साहब एक क्लेरिकल केडर (Clerical cadre) के थेउनके लिए एक नई पोस्ट क्रियेट की जाती है और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट टू दी डाइरेक्टर ओफ एग्रिकल्चर की जगह २५०-२५-५०० की ग्रेड दी जाती है, और उनके ऊपर जितने भी अफसर थे, क्लार्क्स थे उनका हक मार दिया जाता है। इस तरह से नई नई पोस्टें क्रियेटे इसलिए की जाती है क्योंकि वे साहब मिनिस्टर साहब के संबंधी या उनके खास आदमी हैं, उनको वे पोस्टें दी गई।

इसके अलावा में आपका ध्यान कुछ और बातों की ओर भी डालना चाहता हूं। वह यह हैं कि एक महाशय जो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, Assistant to the Director of Agriculture की पोस्ट पर नियुक्त किये गये

थे वे सेक्रेटेरियेट के अन्दर कर्ल्क थे । इस तरह से कई एक पोस्टें इसीलिए क्रियेट की गई थीं कि जो किसी मंत्री के खास आदमी हों या उनके किसी काम के अन्दर कोई हिस्सा लेते हैं उनको दी जाय । इस तरह की बहुत सी एक्जाम्पल्स (उदाहरण) हैं जिसके कारण सरविसेज क्लास में डिस्सेटिसफेक्शन रहता है ।

इसके अलावा, श्रीमान्, में आपका कुछ उन बातों की ओर ध्यान दिलाता हूं कि जिनके कारण बहुत सा आपका रुपया बचत में नहीं हो सका है । हमारे राजस्थान के अन्दर बहुत सी सरविसेज ऐसी हैं जिनको कि अगर ठीक तरह से काम में लिया जाय तो बहुत से पैसे की बचत हो सकती है । जैसा कि जैसलमेर की एक्जाम्पल दे सकता हूं । जैसलमेर में कलेक्टर का आफिस रखा गया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रखा गया है, वहां पर ज्यादा काम नहीं है । अगर वहां पर एस०डी०ओ० का ही आफिस रख दिया जाय तो मैं समझता हूं कि का ी बचत हो सकती हैं और हमारे काफी स्टॉफ की बचत हो सकती हैं । इसके अलावा और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां कि आबादी और क्षेत्रफल बहुत ही कम है; अगर वह सब-डिवीजन में परिवर्तित किये जा सकते हैं तो भी हमारा बहुत सा रूपया बच सकता है ।

इसके अलावा सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस समय जो सरविसेज के अन्दर अनुचित कार्यवाहियां हो रही हैं, वे कार्यवाहियें ऐसी हुई हैं कि कोई भी मिनिस्टर किसी कृपा पात्र को नियुक्त करना चाहता है तो पहले उसको आफिशियेटिंग रखता हैं, आफिशियेटिंग में कुछ काम कर लिया तो उसे परमानेन्ट कर दिया जाता है । इस तरह से वे, जो उनके मन के मुताबिक काम करता है उनको प्रमोशन दे देते हैं ।

इसके अलावा, श्रीमान, कुछ मंत्रियों को, जो बाहर के हैं उनको खुश करने के लिए यहां पर उनके रिश्तेदारों को बुला लिए जाते हैं और अच्छी अच्छी पोस्टें दे देते हैं; जिसका एक्जाम्पल डाइरेक्टर आफ पब्लिक रिलेशन्स का ले सकते हैं ।

इसके अलावा इसके पहले कि मैं लॉ और सिक्योरिटी पर अपनी नजर डालूं, श्रीमान्, आपके सामने एक तस्वीर खींचना चाहता हूं और वह तस्वीर इसी जयपुर शहर की है उसकी घटनास्थली यही जयपुर है और उसके पीछे हैं अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड । श्रीमान् वह तस्वीर बहुत ही दुख:मय तस्वीर, है और वह तस्वीर है लुटेरों के लूट की । उस तस्वीर के अन्दर किसी आदमी के दवारा कोई लूटा नहीं जा रहा है, परन्तु सरकारी कर्मचारियों द्वारा और सरकार का बोझ जिन पर दिया है, वह भी लुटेरों की लूट में शामिल हैं और लूट रहे हैं । वह लूटते है जमीनों के प्लाटों की लूट । इस लूट के अन्दर क्या मिनिस्टर महोदय, क्या सरकारी कर्मचारी सब हिस्सा ले रहे हैं । वह एक बहुत ही विचित्र तस्वीर है, श्रीमान् जयपुर की जनता चाहे उस तस्वीर को नहीं देख पायी लेकिन हम राजस्थान के एक कोने में बैठे हुए लोग उस तस्वीर को बडी तीव्र गति से देख रहे थे ।

और वह तस्वीर बहुत ही दुख:मय प्रतीत हुई । श्रीमान इस तस्वीर के अन्दर बहुत मे तरह तरह के प्लॉट्स हैं, कुछेक नामी प्लॉट्स हैं, जिनकी आमदनी बहुत सी हो सकती है । इस तस्वीर के एक कोने में मिनिस्टर के आदमी हैं, दूसरे में कुछ राजकर्मचारी प्रतीत होते हैं । इसी तस्वीर के एक कोने में एक महाशय हैं जो कि व्यापारी वर्ग के हैं जो जोधपुर में मोटरों का व्यापार करते हैं, वे उस तसवीर के अन्दर, बड़ा सा प्लाट लिये हुए हैं जो प्लाट लाखों रुपयों का है; जिसकी कीमत अगर सही तौर से दी जावे तो उसका २ लाख रुपया हो जाता है । तीसरी ओर श्रीमान् जो तसवीर दिखाई गई है वह है हमारे कुछ एक अखबार क मालिक जिनको कांग्रेसी सरकार अपनाये जा रही है; वे हैं कांग्रेसी अखबार।उनको एक बड़ा भारी प्लाट दिया गया। उनके स्वर से ऐसा मालूम हो रहा था कि वह उनको पारितोषिक के रूप में दिया गया हो ।

दूसरी एक विचित्र घटना है, बहुत दु:खदायी घटना है, जो गत मिनिस्टरी में मिनिस्टर थे उनके प्लाट भी यही बातें बता रहे थे । वे मिनिस्टर महोदय, इस तसवीर के अन्दर बहुत तेज गति से, बहुत अच्छे अच्छे प्लोटों के लिये, जो बहुत अच्छी स्थिति के हैं, दौड़ रहे हैं। यह बहुत असन्तोषजनक चीज है । इस तसवीर के एक कोने में, सामने एक मिनिस्टर महोदय खड़े हुए हैं जो चश्मा लगाये हुए हैं, कुछ मोटे हैं;सारी तसवीर देख रहे हैं;उनको दु:ख हो रहा है यह देख कर । परन्तु वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं। इनके पास सामने अखबार वाले खड़े हैं उस बेचारे को मालूम तक नहीं हुआ यह क्या दशा हो रही है । इस तसवीर के सामने एक दूसरे कोने में जयपुर के नागरिक खड़े हैं वे अंगुलिया उठाकर कह कहे हैं कि जयपुर में Popular मिनिस्ट्री बनी तब राजस्थान में प्लाटों की लूट हुई थी; परन्तु इस लूट ने तो उस लूट से भी कमाल कर दिया । श्रीमान् यह जो तसवीर मैंने हाउस के समक्ष रखी है वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं रखी है यह एक बड़ी कहानी है। इस कहानी के लिए आपके द्वारा मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में जांच करायें। इससे लाखों रुपयों का सरकार का घाटा हुआ है । उसकी जांच करके इस तसवीर को ठीक बनाया जाय ।

श्रीमान् मैं एज्युकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । शिक्षा के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं । शिक्षा की तरफ हम नजर दौड़ायेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि आजकल जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में रखी गयी है वे किस तरह की है। मैं कल एक पुस्तक को देख रहा था जिसका नाम "साहित्य सुधा पहला भाग"है; जो पांचवी कक्षा के लिए रखी हुई है। उसमें सब से पहले गांधीजी की तसवीर है। मैं उसे देखकर खुश हुआ कि आज मुझे महात्मा गांधी की तसवीर देखने को मिली । उस पाठ्य-पुस्तक को मैं देख रहा था। उसमें एक पाठ था "कांग्रेस की कहानी"। मैं अचम्मे में पड़ गया कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को गन्दी पोलिटिक्स पाठ्य पुस्तकों द्वारा सिखाई जाती है। उस कहानी को पढ़ कर मुझे नाजी जर्मनी की याद हो आई । वह बात हिटलेराइट मेथड्स ओफ नाजी प्रोपेगेन्डा की थी। नाजी प्रोपेगेन्डा जब जर्मनी में हो रहा था उसी तरह का प्रोपेगेन्डा हमारी कांग्रेस सरकार इस प्रकार की पुस्तकों को

पाठ्यक्रम में रख कर रही है। राजस्थान की पाठ्य-पुस्तकों द्वारा हमारे छोटे छोटे बच्चों को सिवाय पोलिटिक्स के और कुछ नहीं सिखाया जाता है; जब कि हमें बच्चों को पोलिटिक्स (राजनीति) से बिलकुल अलग रखना चाहिये। इस तरह से बच्चों का भविष्य खराब किया जाता है; इन गन्दी पाठ्य-पुस्तकों द्वारा। इसके अलावा अब आपके सम्मुख सिक्योरिटी पर, जो हर सरकार का पहला फर्ज है, कुछ कहूंगा। इस समय हमारे प्रांत में डाके हो रहे हैं पुलिस की कमजोरी है। इसके बारे में कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा। यह हर गवर्नमेन्ट का ध्येय है, मकसद है कि वह अपने प्रान्त में अमन चैन रखे, शान्ति रखे और शान्ति और सुविधा के लिए जो भी कार्य किया जाय, करे।

श्रीमान् में आखिर में वित्त मंत्री के उन शब्दों को दोहराते हुए, अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं कि हमारी सम्पूर्ण कहानी मुसीबतों से भरी हुई है। साथ म यह भी बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की मुसीबत की नौबत ही नहीं आती यदि पहले से ही काय ठीक तरह होता।

श्री संग्रामसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट का दिन हर देश व प्रान्त के लिए बड़े महत्व का दिन होता है। जहां उस राज्य के बजट को प्रस्तुत किया जा रहा हो जनता को उत्साह होता है कि हम हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा कई बातें सुनेंगे; अव्वल यह कि हमारे प्रांन्त की आर्थिक दशा कैसी है वह सन्तोषजनक है या नहीं; दूसरे जो कुछ कर मौजूदा चल रहे हैं उनमें क्या कमी की जायगी और कर नये तो नहीं लगाये जायेंगे।

मुझे अफसोस होता है कि इन तीन बातों के लिएं उन्होंने जो कुछ कहा; जनता को सन्तोष नहीं हुआ। अव्वल में आर्थिक स्थिति के मुत्तल्लिक बातें कहूंगा। जो बजट पेश किया गया है उसमें करीब १ करोड़ यानि ९३॥ लाख का घाटा दिखलाया गया है। यह घाटा कोई छोटा घाटा नहीं है; बहुत बड़ा घाटा है। दूसरी ओर जो कुछ कोष मौजूद था उसको हर तरह से उड़ाया जा रहा है; उसके लिए बड़ा दुःख होता है। एकीकरण के वक्त जो रियासतें पहले थीं उनमें से हर रियासत ने कुछ न कुछ, किसी ने ५ करोड़, किसी ने चार करोड़, किसी ने २ करोड़ रुपया राजस्थान को दिया। वह सब मिलाकर कुल १७ करोड़ रुपया का धन मिला। लेकिन हम देखते हैं कि इन तीन सालों में उसमें से बहुत सा खर्च कर दिया गया। उसके आलावा इम्पीरियल बैंक से ९ करोड़ का ऋण हमारे सिर पर हो गया वह हर साल बढ़ता बढ़ता अब ९ करोड़ के करीब हो गया। अगर इससे भी ज्यादा होता तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता। यदि यही रुपया प्रोडक्टिव कामों में लगाया होता तो आज हमें इम्पीरियल बैंक द्वारा लिये गये ९ करोड़ रुपये के ऋण पर सालाना ३३ लाख रुपया ब्याज नहीं देना पड़ता। इससे हमें क्या फायदा हुआ। इसी तरह आप यहां देखें करों के मुतल्लिक तो मालूम होगा कि मौजूदा करों में कोई कमी नहीं हुई और इसके अलावा नये कर आने वाले हैं। हां, जहां जरूरी होता है वहां पर कर भी लगाने पड़ते हैं। पर यह देखना होता ह कि उससे जनता को क्या फायदा होता है। इन नये करों से जनता को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि जहां तक हम देखते हैं नुकसान होगा। हम नये कर

लगावें; मगर उससे पहले हमें जनता को संतोष दिलाना होगा कि जो कर लगाए जा रहे हैं उससे जनता को लाभ होगा । नये कर लगाने से पहले यह अच्छा होगा कि फज़ूलखर्ची में कमी की जाय। जब हम देखेंगे कि नये कर लगाना ठीक है तो नये कर भी लगावेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बड़ी रकमें जो खर्च की जाती हैं वह बेकार जाती है और उसके लिये जनता की बहुत सी शिकायतें होती हैं । हमें यह देखना है कि जो रूपया जहां के खर्च के लिये दिये जाते हैं वाकई वे रूपये खर्च होते हैं या नहीं । पी० डब्लू० डी० को पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट के नाम से कहा जाता है। मैं यह कहूंगा कि लोगों का कहना बहुत हद तक ठीक है। आप सड़कों की हालतों को देखिये । आज नई नई सड़कें बनाई जाती ह; वे बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसका कारण यह है कि जितना रुपया खर्च होता है पूर्ण रूप से नहीं लगाया जाता । इसी प्रकार आप बिल्डिंग्स की हालतों की देखिए । कितने रूपये खर्च किये जाते हैं और यहां तक होता है कि नई बिल्डिंस बनती है; उसी साल उसकी रिपेयर्स के लिये रकम रखी जाती है । यह इस लिए रखी जाती है कि वे लोग जानते हैं कि काम खराब होता है और वह बिल्डिंग एक साल भी नहीं चल सकती है । पानी का हाल देखिये, लोगों को कैसी परेशानियें और दुविधाए हो रही हैं । पानी पहुंचता नहीं। बिजली का हाल देखिये। पहले बिजली के महकमे से सरकार को हमेशा फायदा रहता था। अब हर जगह घाटा रहता है । खर्चा भी होता है और घाटा भी है और लोगों को फिर कोई लाभ नहीं पहुंचता और न उसको सुख ही मिलता है । लोगों को हर वक्त तेल का इन्तजाम रखना पड़ता है; न मालूम किस वक्त बिजली बन्द हो जाए; इसका कुछ पता नहीं रहता।

किसी भी गवर्नमेन्ट को सूचारू रूप से चलाने के लिए चार बातें खास खास होती है ।

१. अच्छी माली हालत का होना । इसके लिए तो आपने देख ही लिया कि सरकार की माली हालत कैसी है और पिछले तीन साल से कैसी रही है। पहले भी कांग्रेस सरकार थी और अब भी है । इसलिए आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कांग्रेस सरकार दोषी नहीं, यह तो हम नहीं कह सकते ।

२. दूसरी लाजमी चीज यह है कि एफिशियेंसी ओफ दी एडमिनिस्टेशन। अगर इफिशियेंट गवर्नमेन्ट नहीं होगी तो काम नहीं चल सकता । हमें यह कहा जाता है कि कौंसिलर और एडवाईजर्स जो मुकर्रर होते हैं, नहीं होने चाहिए । हम भी यह चाहते हैं कि वाकई में नहीं होने चाहिए और इनका खर्चा क्यों लगाया जाता है । लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो सरकार है वह काम करने योग्य नहीं है । अयोग्य साबित हो तो फिर वगैर एडवा-इजर्स और कौसिलर्स के कैसे काम चलेगा ? मैं यह कहूंगा कि यहां भी कांग्रेस सरकार है और एडवाइजर और कौन्सिलरों को भी सैंटर की सरकार ने ही मुकर्रर किया है, वे जानते है कि इनके वगैर शासन, कांग्रेसी मंत्री मंडल चला नहीं सकता, इसलिए मुकर्रर किया है । हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी एड-

वाइजर्स और कौन्सिलर्स यहां से हटाए जावें मगर "फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर"। पहले आप उसके पात्र बनिये और फिर उसकी इच्छा करिये। जब मालूम हो जायगा कि आप उनके बगैर काम चला सकते हैं तो बहुत जल्दी ही उन्हें हटा दिया जावेगा ।

३. तीसरी चीज है करप्शन । कोई भी सरकार, जब तक सरकार में करप्शन चलता रहेगा, अच्छी सरकार नहीं बन सकेगी और उससे पब्लिक को कोई लाभ नहीं होगा। आप अपने बजट में रुपया रखते हैं वह रुपया जाता कहां है। जहां जाना चाहिये पहुंचता नहीं । बीच का बीच में उड़ जाता है। पुलिस पर दो करोड़ अस्सी लाख खर्च लगा रखा है; मगर फिर यह हाल है कि रोज चोरियें होती हैं और पहले से ज्यादा न चोर पकड़े जाते, और न माल बरामद होता है । पुलिस का इन्तजाम कतई ठीक नहीं । पुलिस अपना कर्त्तव्य नहीं कर रही है । पुलिस वाले चोरी करने वालों से मिल जाते हैं फिर पब्लिक को बचाने वाले कौन ? यह हाल करप्शन का है । जब तक आपके काम करने वाले अच्छी तरह और इमानदारी से काम नहीं करेंगे; बजट में घाटा ही घाटा रहेगा । हम कभी भी नये कर लगाने के लिये तैयार नहीं; क्योंकि पब्लिक हमसे पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे । वे कहेंगे कि आपने क्यों नहीं देखा कि कर लगाना वाजिब है या नहीं । अब तक यह कहा जा सकता था कि गवर्नमेन्ट अपनी नहीं थी। अब हमारी है; हमारा फर्ज है कि जो फजूल खर्ची हो रही है उसको रोकें ।

हर साल आप बजट में रकम बढ़ाते हैं और यह दिखाते हैं कि इस साल शिक्षा पर इतना रुपया, चिकित्सा पर इतना रुपया रखा है; लेकिन वाकई में जो खर्च होता है उसका उपयोग ठीक है या नहीं । स्कूलें खोलते हैं लेकिन यह नहीं देखा जाता कि आया काम ठीक होता है या नहीं। मकान है तो कुर्सी नहीं; मेजें हैं तो कलम दवात नहीं । ऐसी स्कूलों से क्या फायदा ? यह सिर्फ प्रपोगेंडा या दिखावे के लिए है कि हम तरक्की कर रहे हैं । खाली दिखावे से काम नहीं चलेगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि जो कुछ किया जारहा है पब्लिक के फायदे के लिए हो रहा है; जो कुछ रुपया लगाया जाता है वह जनता तक पहुंचता है हैं या नहीं ।

दूसरी तरफ मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जागीरों के बारे में जो कहा जा रहा है, इस संबन्ध में गल्त फ़हमी हो रही है । चीफ मिनिस्टर ने और राजप्रमुख के भाषण में जैसा कहा गया है कि हम जागीरदारों से कोओपरेशन चाहते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक साहबने उधर से यह कहा कि इन बातों से, सरकार की कमजोरी साबित होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके ख्याल में अगर यह कमजोर है तो आप वीरता का रास्ता बतावें । हम आपको कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि इस समस्या को सुलझाने के लिये हम तैयार है । डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों के अनुसार यह काम किया जाय और समस्या को हल किया जाय और किसी पर जबर्दस्ती नहीं थोपा जाय । श्री मावलंकर, जो हमारे माननीय अध्यक्ष संसद के हैं उनके

शब्द में आपको सुनाता हूं:-

"Democracy means conversion by arguments and Persuasion and not suppression by use of superior force. Unless we realize this we have no hope for democracy in India."

(चियर्स)

अब डेमोक्रेसी है और चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों पर चलें । डेमोक्रेसी में सब की राय से काम होता है। यह नहीं होता कि किसी पर कोई चीज जबरदस्ती थोपी जावे। चूंकि मैंने समय ज्यादा ले लिया है इसलिए अब मैं ज्यादा न कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

(चियर्स)

श्री रामदयाल उपाध्याय:- अध्यक्ष महोदय, मैं ने श्री वित्त मंत्रीजी का भाषण सुना और उसके पश्चात् बजट (आय-व्ययक) को भी अच्छी तरह से पढा। जब मैं उसे पढ रहा था तो एक दम मेरा विचार हुआ कि इस बजट (आय-व्ययक) का टाइटल—हेडिंग (शीर्षक) बजट एस्टीमेट्स फोर राजस्थान (राजस्थान का आय-व्ययक आगणन) जैसा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि यह एक दु:ख भरी कहानी है, शायद यह कहने के कारण ही इसका टाइटल हेडिंग (शीर्षक) श्री वित्त मंत्रीजी सही नहीं कर सके हैं । मेरे ख्याल से इसका हेडिंग (शीर्षक) यह होना चाहिये था कि बजट एस्टिमेट्स आफ राजस्थान टाउन्स एंड सिटीज। (राजस्थान के शहरों तथा नगरों का आय-व्ययक आगणन) क्योंकि जैसा कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है, कि ७१ % आय हमारे यहां करों से होती है और वे कर अधिकतर गांवों से आते हैं। तो उन्हें यह भी सोचना था कि जितना हम गांवों से लेते हैं उसी हिसाब से किसी न किसी रूप में गांवों पर खर्च करना चाहिये। मुझे हर्ष है कि शिक्षा के मद में २० लाख रुपये इस वर्ष पहले से अधिक खर्च किये जायेंगे; लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वे २० लाख रुपये यदि गांवों के लिये खर्च करें तो अति उत्तम होगा क्योंकि राजस्थान के गांव हमारी तरफ, सदन की तरफ आंख उठाये देख रहे हैं और हर एक ग्रामीण यह चाहता है कि मेरे बच्चे शिक्षित हों और वे भी नगरवालों की तरह हर तरह के साधन जो नगरवालों को दिये गये हैं, वे भी प्राप्त करें। शिक्षा के लिये शहरों में कॉलेजेज, होस्टल बिल्डिंग्ज और पुस्तकालय आदि कई तरह की सुविधायें दी गई हैं लेकिन यह नहीं बतलाया गया है कि गांवों में कहां स्कूलें खोली गई हैं। विद्यार्थियों को नई एक्टिविटीज (कर्मण्यता) की तरफ लगावें जिससे कि उनको व्यवहारिक ज्ञान हो, शासन का ज्ञान हो और भी नई बातों का ज्ञान हो; ऐसा कोई विचार उनके लिये नहीं रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का ध्यान मेडिकल (चिकित्सा) की ओर आकर्षित करूंगा कि यह सच्च है कि जो मेडिकल (चिकित्सा) व स्वास्थ्य के साधन नये

नये शहरों में सजाये जाते हैं उसका एक पैसे भर भी गांवों के लिये खर्च नहीं किया गया है। गांवों के लोग साधारण मलेरिया, साधारण बिमारी से टसक टसक कर मर जाते हैं परन्तु गांवों में उपचार का कोई नया तरीका नहीं काम में लाया गया। शहरों में दो चार होस्पिटल होते हुए भी नये बनाये जाते हैं इसलिये मैं कहूंगा कि हमारा बजट नगरों की तरक्की बढ़ाने का बजट है। इसके बाद जहां तक म्यूनिसिपेल्टियों (नगर पालिकाओं) और ग्राम पंचायतों का ख्याल है, सरकार ने जो ग्रेड (श्रेणियां) म्यूनिसिपेल्टियों (नगर पालिकाओं) को दी है उनसे कहीं कम ग्राम पचायतों को दी है। ग्राम पंचायतें उतनी सेल्फ सपोर्टिंग (आत्म निर्भर) नहीं है जितनी कि म्यूनिसिपेल्टियां (नगर पालिकाओं) हैं लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान नहीं दिया गया। शायद जैसा कि सदन में किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि यह बजट नौकरशाही का बजट है; यह उसकी नकल है जो सदा से बनता आया है इसलिये मालूम होता है कि उनको गांवों की चिन्ता नहीं है। अभी एक महाशय ने कहा था कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर (पहले आप उसके पात्र बनिये फिर उसकी इच्छा करिए); इसके लिये प्रार्थना है कि एक तरफ तो कहते हैं कि करपशन (भ्रष्टाचार) समाप्त हो और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पर कोई मशीनरी लादी जाय और फिर यह कहते हैं कि हमको बजट में वही चीज मिली है जो आज तक मिलती आई है। मैं कोई तथ्य उनके कहने मे नहीं समझता क्योंकि यह वही चीज है जो अंग्रेज हमे कहा करते थे कि फर्स्ट डिजर्व, देन डिजायर। (पहले आप उसके पात्र बनिये फिर उसकी इच्छा करिये)। अध्यक्ष महोदय, ऐसा हमारे सदन के सभी सदस्य कहते हैं कि प्रत्येक कार्य को करने के लिये होशियारी और ईमानदारी हो लेकिन जो कुछ अंकुश हम पर लगा हुआ है यदि वह दूर किया जाय तो मैं समझता हूं कि जो कुछ हम चाहते हैं वह शायद शीघ्र ही संभव हो सकता है।

इस बजट में जागीरदारी के सम्बन्ध में जो कुछ बताया गया है उसके साथ यह बताना आवश्यक है कि जागीरदारी समाप्त की जा रही है और उससे इतने रुपयों का लाभ होने वाला है। इससे मालूम होता है कि सरकार इस संबंध में जो एक्ट (अधिनियम) पास कर चुकी है उसे इस वर्ष लागू करने का विचार नहीं कर रही हैं इसलिए इस बारे में जो प्रकाश डाला गया है, मैं प्रार्थना करता हूं, कि इस एक्ट को लागू करने पर विचार करें। इससे अधिक मैं नहीं कह सकता। मैं प्रार्थना करूंगा कि गांवों के उत्थान के लिये बजट में बहुत कम रकम प्रोवाइड (रखी) की गई है जो कि अधिक प्रोवाइड (रखी जानी) होनी चाहिये।

श्री भैरवसिंह (सराड़ा सलूम्बर):–माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट दर असल में बहुत महत्व की चीज है और उसे समझना तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। मेरे बोलने में जरा अंग्रेजी की दिक्कत आवे तो मैं माफी चाहूंगा। मुझे हिन्दी बोलने का अभ्यास नहीं है। इस बजट के बारे में यहां चारों तरफ से आवाज आती है। दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा गया है कि यह पुरानी तर्ज का नौकरशाही बजट है और यह बजट कई नई स्कीमों (योजनाओं) और सोशियल रिफोर्म्स (सामाजिक सुधार) का बजट होना चाहिये था परन्तु एसा

नहीं है, इसके लिये मुझे खेद है। हमारे प्रजातंत्र के समय भी ऐसे ही चलेगा तो यह एक गलत परम्परा (ट्रेडिशन) हो जायगी। इसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिये, ताकि हमारा आयन्दा बजट नौकरशाही से बनाया हुआ न हो बल्कि नये तरीके का और नई चीज को सामने रखते हुए बनाया जाय। हमारे यहां सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट (केन्द्रीय सरकार) द्वारा थोपे हुए बड़ी २ तनख्वाहों (वेतन) आई. सी. एस. यहां होने से टोप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन (बहुत ही खर्चीला शासन) हुआ है। इतना हेवी एडमिनिस्ट्रेशन (भारी प्रशासन) नहीं होता और हमारे यहां के छोटी तनख्वाहों वाले रखे जाते तो हमें फायदा होता। हमारे यहां जब मर्जर (विलीनीकरण) हुआ था, फोरमर (पूर्व) राजस्थान में, तब हमें बतलाया गया था कि छोटी रियासतों व जागीरों की बनिस्पत अगर सब मिलकर बड़ा मुल्क बनाया जायगा तो हमें अधिक फायदा होगा। लेकिन बड़ा राजस्थान बन जाने से छोटे २ युनिटों (एककों) को भी नुकसान हुआ और लोगों की तकलीफें रफा नहीं हो सकीं। जब अलग छोटे युनिट थे तब वहां के अपने सेक्रेटेरियट (सचिवालय) थे, कोर्ट (न्यायलाय) थे, अस्पताल थे शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध था, लेकिन जैसा कि बतलाया गया है बड़ा युनिट होने से सुख सुविधायें ज्यादा बढ़ेंगी और खर्चा कम होगा लेकिन हम देखते हैं कि इससे खर्चा ज्यादा बढ़ गया। छोटे युनिटों (एककों) से होने वाले फायदे चले गये और इन्तजाम कम्पलीट फेल्योर (पूर्ण असफल) रहा। वे इसमें अकलमंदी समझते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इससे खर्चा बढ़ गया। तनख्वायें बढा दी गईं और वेतन बढाने पर भी सिविल सरवेन्ट्स (नागरिक सेवक) खुश नहीं। ऊंची जगह जो काम करते थे उनको नीची जगह रखा गया और जो ३००) रु० पाते थे उनके ५००) रु० हो गये। आफिस (कार्यालयों) में असंतोष होने से कामयाबी नहीं हुई। काम का आउटपुट (निकाला जाना) भी कम हो गया। जैसा काम वे छोटे छोटे युनिटों (एककों) में करते थे वैसा यहां नहीं करने लगे। नतीजा यह हुआ कि फाइलों का भार बढ़ गया। मैं यह अर्ज करूंगा कि अंग्रेजों के समय से सफेद हाथी बांधने की कहावत थी वही आज यहां लागू हो रही है।

तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इंटिग्रेशन (एकीकरण) फेल (असफल) हुआ। इस फेल (असफल) होने के बारे में मैं मेवाड़ का जिक्र करता हूं। जिस समय इंटिग्रेशन (एकीकरण) हुआ था, मैं भी उसमें था, मैं अपने आपको बहुत बड़ा नहीं मानता; पर मुझे भी हिस्सा मिलता है, उस वक्त हमसे यह कहा गया था, हमसे ये वायदे किये गये थे कि तुम्हारा इन्तजाम ठीक नहीं है इसलिए एक इकाई के रूप में इसे बना रहे हैं, जिससे सारा इन्तजाम ठीक हो सकेगा, अस्पताल, शिक्षा, और सभी तरह का इन्तजाम एक साथ होने से काफी फायदा होगा। लेकिन मैं आपको अर्ज करूंगा, मेरे गांव के बारे में कि वहां की क्या हालत हो गई है। यह कहते हुए मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। वहां जो एक टूटी फूटी डिस्पेंसरी थी जिस में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ही तरह की दवाइयां मिल जाया करती थीं, वह भी अब खतम हो गई है। इंटिग्रेशन होने के बाद से मेवाड़ की हालत दिनो दिन गिरती हुई ही जा रही है। स्कूलों की हालत तो और भी खराब हो गई है। हमारे वहां दवाई का नामो निशान भी नहीं है, छोटी से छोटी दवाई भी नहीं मिलती, उसकी

जगह हमें इस एटम (अणुबम) युग में पुरानी मेडिकल (चिकित्सा) से काम लेना पड़ता है । अगर किसी का लिवर (फेफड़ा) खराब हो गया तो उसके इलाज के लिए उसे जलाया जाता है । इस नये युग में जब कि कई नई २ औषधियां हैं वहां हमारे यहां पर वे ही पुराने साधन काम में लाये जाते हैं । अगर किसी के मुंह में खराबी हो गई तो उसके मुंह में गरम करके बेलन डाला जाता है तो मैं कहूंगा कि इस तरह के इलाज रोकने चाहिए । लेकिन वहां जानवरों की तो दूर रही आदमियों तक की भी हालत अच्छी नहीं है । इस तरह छोटे युनिट (एककों) में जो हम लोग थे तो वहां हमें ज्यादा सुख सुविधायें थी । अभी मेरे एक मित्र ने कहा था कि जागीरदारों से पैसा ले लिया जाय लेकिन मैं कहता हूं कि इंटिग्रेशन (एकीकरण) के समय हमसे बहुत कुछ लिया गया फिर भी इन्तजाम ठीक नहीं कर सके, हालत खराब होती ही गई ।

अब मैं आपको शराब के बारे में कुछ कहूंगा । सब इसकी निन्दा करते हैं, सब कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए । सरकार इस पर बराबर टेक्स (कर) बढ़ाती जा रही ह बढ़ाये, जरूर बढ़ाये, पर इसके लिए कुल सोचने की भी जरूरत है, समझने की भी जरूरत ह । जब से शराब पर टेक्स (कर) लगा है यह दिनो दिन बढती जा रही है। हमें यह देखना है कि इसकी आमदनी दिनों दिन बढ़ती क्यों जा रही है ? इसका कारण ही यह है कि शराब पीना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जब से टेक्स (कर) बढ़ा है लोगों ने अपने यहां शराब बनाना शुरू कर दिया है । वे लोग केवल बनाते ही नहीं हैं. अधिक बनाकर बेचते भी हैं । इस प्रकार इसके रोकने के बजाय यह तो और भी अधिक बढ रही है और इन टेक्सों (करों) का असर पड़ रहा है, गरीब जनता पर। इस शराब को बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, कोई भी आदमी आसानी से अपने यहां इसे बना सकता है । इसका तरीका इतना सरल है कि आदमी बहुत जल्द सीख सकता है । अगर आप भी सीखना चाहें तो मैं आपको दो मिनिट में इसे सिखा सकता हूं। गन्ने के रस से इसको बनाया जाता ह । तो इसका असर यह होता है कि जहां आप एक ओर टेक्स बढाकर इसे कम करने की सोचते हैं वहां दूसरी ओर यह अधिक बढती जाती है । अगर आप इस पर टेक्स (कर) बढ़ाते हैं तो जो पीने वाले हैं वे लोग पियेंगे ही और अधिक पियेंगे और इसके लिए फिर चारों ओर चोरबाजारी फैलेगी, पैसों के लिए चोरियां होंगी ।

श्री भवानीशंकर:-ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से मेरे माननीय मित्र बोल रहे हैं उनकी जानकारी से हाउस को ऐसा पता लगा कि शायद शराब बनाने या उसे निकालने में आप एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) हैं और इस प्रकार की चीजें, अध्यक्ष महोदय, जनता के लिए या हाउस के लिए हितकर नहीं हो सकती ।

श्री भैरवसिंह:-मेरा कहने का मतलब तो यह था कि इस शराब पर टेक्स (कर) लगा कर हम इसको जितना ही रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही

यह अधिक बढ़ता जाता है। जितना आपने टेक्स (कर) लगाया उतनी ही आपकी आमदनी बढ़ी, इसका मतलब यह हुआ कि यह दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

यह एक ऐसा टेक्स (कर) है जिसे सोच विचार कर लगाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि एक हिस्से को दबायें तो दूसरा उधर निकल जाय। जिस तरह कि एक अनएक्सपर्ट (अयोग्य) मोच निकालने वाला होता है, वह एक तरफ की मोच निकालता है, तो दूसरी तरफ मोच निकल जाती है, लेकिन जब एक एक्सपर्ट मोच निकालने वाला होता है वह बराबर दबाकर मोच निकाल देता है। इसी तरह टेक्सेज (करों) को ले लिया जाय। इस तरह के जो टेक्स देना पड़ता है उनके रिपर्कशन्स (प्रतिफल) बुरे होते हैं। इसको अच्छी तरह से सोच कर करना पड़ेगा। बाकी वैसे तो मैं कहता हूं कि इसको आज ही खत्म कर दिया जाय तो बैस्ट (अत्युत्तम) है। अगर इसको जिन्दा रखने में बहुत से लोगों में डिस्सेटिस्फेक्शन (असन्तोष) है, यह खराब चीज है तो। मेरा खास तात्पर्य तो यह है कि अगर आप इसको और दृष्टि से देखें तो यह आपकी इच्छा है। तो इस तरह से अब मैं आपको यद्यपि इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है, यह बताऊंगा कि अगर आप इसे बन्द ही करना चाहते हैं, तो उससे कई आदमी बेकार होंगे जो कि पीढ़ियों से इस धन्धे को करते आये हैं, उनके एम्प्लॉयमेन्ट (नौकरी) के विषय में भी गवर्नमेन्ट (सरकार) ने कुछ सोचा है और कोई स्कीम (योजना) अपने बजट में रखी है। इसके बन्द नहीं होने पर भी ठेके होने के कारण कई आदमी अनएम्प्लॉयड (बेनौकरी) रह जाते हैं। कुछ लोग मेरे पास आये थे। उन्होंने इतने दुःखी होते हुए कहा कि वे पहले ही दिवालिये हो चुके हैं। फिर ये अनएम्प्लायड (बेनौकरी) हो जायेंगे तो कहां जायेंगे। उनके पास कोई आल्टर्नेटिव (वैकल्पिक) धन्धा नहीं है। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए इस पर विचार किया जाय।

जब हमारे यहां सड़कें बनीं और मोटरें चलीं तो सरकार ने सोचा कि तांगे वाले बेकार हो जायंगे, तो उन्होंने उस टुकड़े पर मोटर चलाने की इजाजत नहीं दी। अगर यह परिस्थिति है, अगर यह खयाल है तो हमारी इन्डस्ट्रीज डेवुलप (व्यवसाय उन्नतिशील) नहीं होगी। कॉटेज इन्डस्ट्रीज (घरेलू धंधे) से कम्पीटिशन (प्रतियोगिता) तो चलता ही रहेगा और हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। कांकरोली में रोड़ बनाई गई है, लेकिन फिर भी १।। मील के टुकड़े पर तांगे में जाना पड़ता है, चाहे कांकरोली तक ५० मील तक मोटर आजाय, लेकिन १।। मील तक तांगे में जाना पड़ेगा। अगर कुछ कहा जाता है तो वे कहते हैं कि हम तांगे वालों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। कोई आदमी किसी को नाराज नहीं करना चाहता है। अगर यह पालिसी (नीति) गवर्नमेन्ट (सरकार) की रही तो किसी को खुश नहीं बना सकती है। हमें डेफिनिट स्कीम (निश्चित योजना) लेकर चलना पड़ेगा। बजट बनाने में भी वैसा ही होना चाहिए।

हमारे मंत्रियों और हमारे छोटे से छोटे नौकरों के वेतन में कितना अन्तर होना चाहिए; यह भी देखना होगा। १० या २० गुने से यह ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह जो चीज है कि हमारे यहां चपरासी को ४०) रु० मिलते हैं और सेक्रेट्रियों

(सचिवों) और एडवाइजरों को (परामर्शदाताओं) २।।, तीन हजार वेतन के दिये जाते हैं, शायद हमारे मंत्री महोदयों को तो १००० रु० ही मिलता है । नो डाउट (कोई सन्देह नहीं) मंत्रियों को वेतन २० गुना ही मिलता है, लेकिन अगर २० गुने से ज्यादा का अन्तर रहता है तो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है; वह अन्तर मिटना चाहिए । बस मैं यही अर्ज करूंगा ।

श्री सोहनलाल:—माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े ही हर्ष का विषय है कि राजस्थान की चुनी हुई धारा सभा के सामने हजारों वर्षों के बाद आज प्रथम बार बजट (आय--व्ययक) रखा गया है। इस बजट (आय-व्ययक) के भाषण को मैंने पढ़ा और साथ ही जो बजट के एस्टिमेट्स (आगणन) सरकार की तरफ से दिया गया है उन्हें भी मैंने देखा है । इन एस्टिमेट्स (आगणनों) को देखने के बाद मेरे हृदय में हर्ष और निराशा दोनों की ही भावना एक साथ आन्दोलित हुई ।

जब बजट (आय--व्ययक) किसी विधान सभा के सामने आता है तो सबसे पहले देखने की जो वस्तु होती है वह यह है कि इस बजट (आय--व्ययक) में जनता के ऊपर नये टेक्सेज (कर) क्या रखे हैं, और जो खर्चा रखा गया है वह जनता की सुख सुविधा के लिए किस तरह से रखा गया है । इन दोनों दृष्टिकोणों से अगर इस बजट को हम देखें तो हम यह कह सकते हैं कि यह बजट जनता की सुख सुविधा के लिए बनाया गया है । मैं आपको बताऊं कि इस बजट (आय--व्ययक) में जो मुख्य टेक्स नया रखा गया है उससे आम जनता का कोई अहित नहीं होगा; एक वर्ग विशेष का अहित हो सकता है, लेकिन आम जनता के लिए कोई दुःख नहीं होगा। एग्रिकलचर इनकम टेक्स (कृषि-आय कर) के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि लेजिस्लेशन (विधान) हमारे सामने नजर नहीं आया है, इस पर सही सही कुछ नहीं कह सकता हूं, इसलिये कई कई माननीय सदस्यों ने तो यह भी कह दिया है कि यह टेक्स (कर) आम किसानों पर लादा जा रहा है, लेकिन जैसा कि, प्रेसीडेन्ट (राष्ट्रपति) महोदय, हमारे मिनिस्टर, संबन्धित मिनिस्टर बतायेंगे, और जो थोड़ी बहुत रूपरेखा उन्होंने राजप्रमुख के भाषण में दी, उनसे मुझे विदित होता है कि यह जो टेक्स (कर) रखा जा रहा है वह आम किसानों के प्रति नहीं रखा गया है, बल्कि उन मोटे २ जागीरदारों और जमीन वालों पर होगा जो कि बेकार बैठे हुए, गरीब किसानों का शोषण करते हुए, अपने शरीर को बड़ा कर रहे हैं । उन लोगों पर यह टेक्स (कर) असर करेगा। मैं आपको बतलाऊं कि वह इस तरह की बात है जैसा कि शराब के बारे में कहा गया है । इसके बारे में निवेदन करूं कि यह आम जनता के लिए सबसे बड़ी खराबी है और इसको जितना जल्दी से जल्दी बन्द किया जाय उतना ही अच्छा है । इसके बारे में भी जिन लोगों ने कहा है उन्हीं पर इसका ज्यादा असर होता है । तो मैं आपसे आशा करता हूं कि इस टेक्स (कर) के दृष्टिकोण से देखने पर यह बजट रद्दी नहीं कहा जा सकता है ।

इसी तरह से दूसरी बात से, खर्चे के रूप में आपको बताता हूं कि यह बजट मुख्यतया जनहितकारी कार्यों के लिए रखा गया है ।

दूसरी बात मैं आपको उस खर्चे के विषय में बताऊंगा कि इस बजट में मुख्यतया जनहित कामों के लिए रकमें रखी गई हैं। यदि उनको आप देखेंगे तो आपको विदित होगा कि २-३ या ३-४ से कुछ ज्यादा खर्चा जो है वह शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए, सिंचाई के लिए रखा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस बजट में २-३ या ३-४ से ऊपर यानि इतना अधिक हिस्सा बजट का जनहित के कामों के लिए रखा जाय तो क्या आप उस बजट को प्रतिक्रियावादी या जनता का अहित करने वाला बजट कह सकते हैं ? मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर वे तुलनात्मक दृष्टि से उस जमाने के बजटों से मुकाबला करें जब कि सामन्त लोग हम पर शासन किया करते थे, अंग्रेज लोग हम पर शासन किया करते थे, जब कि बजटों पर आवाज नहीं बुलंद कर सकते थे, जब कि वे लोग बजट केवल ब्रिटिश साम्राज्य के इशारे पर रखे जाते थे, जब कि कुछ मदें ही जन हित के नाम से रखी जाती थीं, जैसे सड़कों के लिए जो एस्टीमेट होता था तो वह महाराजा साहब के शिकारगाह तक जाने वाली सड़कों का होता था, यदि बिल्डिगों के लिए एस्टीमेट इसमें रखा जाता था तो वह रुपया काम में लाया जाता था अपनी मरजीदारों के मकान बनवाने में। आज हमारे सामने राजस्थान का बजट है जिसमें जिस किसी मद में रुपया रखा गया है वह रुपया उसी मद के लिए खर्च किया जायगा जिसके लिए कि वह रखा गया है। दूसरी के रूप में वह खर्च नहीं किया जा सकता है।

मैं एक बात अब बताना चाहता हूं कि जागीरी क्षेत्रों में जहां का कि मैं रहने वाला हूं, मुझे भी इसका पूर्ण आभास है कि जागीरी क्षेत्रों में उस जमाने में जो सहूलियतें थीं, मुमकिन हो वह उन भाइयों के (सामने की बेन्चेज की ओर इशारा करके) दृष्टिकोण से ठीक हों। यदि जनता की आम भावना की दृष्टि से देखते हैं तो मैं महसूस करता हूं कि जागीरी जमाने के बनिस्पत आज हमें कई गुना ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। जो जागीरी क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति हैं वे इसको जानते हैं। आज जागीरदार लोग इस सदन में सरकार के सामने यह चीज रखते हैं कि हमारे यहां हाई स्कूल नहीं है, वह होनी चाहिए, हमारे लिए यह चीज चाहिए, वह चीज चाहिए, वह आज जागीर और खालसे के भेदभाव को मिटाकर उस रूप में देखें जिस रूप में सामान्यतया उसको देखना चाहिए, उसको देख रहे हैं। हमारे यहां हाई स्कूलों का निर्माण भी हो रहा है। आज हमें खुशी है कि खालसा और जागीरी क्षेत्रों में कोई भेदभाव नहीं है। अगर उस जमाने की याद दिलाता हूं तो मेरा हृदय आंतकित होता है।

आज की सरकार ने फेमिन रिलीफ (दुर्भिक्ष निवारण) में कितना काम करके दिखलाया है, कितना रुपया खर्च कर रही है। करीब ४५ हजार के लगान की छूट दी गई है। जागीरी जमाने में जनता के हित के कितने कार्य हुए, हमें उन चीजों को देखना है, तुलनात्मक दृष्टि से। किसी भावना या किसी वर्ग विशेष के पक्षपात को लेकर हम सामने नहीं आयें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे और ठंडे दिल से सोचेंगे तो हमें मालूम होगा कि उस जमाने से आज के जमाने में जागीरी क्षेत्रों के रहने वाले व्यक्ति हैं उनको कितना फायदा मिल रहा है।

दूसरे पैसे की दृष्टि से अगर जागीरी क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंची है तो उससे अधिक फार्मर (पूर्व) राजस्थान ने जो तरीका निकाला उससे जागीरी क्षेत्रों के रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मालूम है कि उससे कितना अधिक लाभ पहुंचा है । यदि उस तरीके को आज भी राजस्थान के अन्दर काम में लाया जायगा तो मैं आशा करता हूं कि उससे जागीरी क्षेत्र की दबी हुई जनता बहुत ही कम समय में समृद्धिशाली और खालसा की जनता के समान हो सकेगी।

मैं अब शिक्षा के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। शिक्षा के विषय में जब बजट देखता हूं तो गत वर्ष २५ हाई स्कूल कायम हुए; उससे जनता को काफी लाभ हुआ। लेकिन इस वर्ष के अन्दर कोई नये हाई स्कूल का प्रोविजन (प्रबन्ध) नहीं रखा गया । आगे ही जो हाई स्कूल खुले हैं उनमें न अच्छे अध्यापक हैं न अच्छा सामान ही है उसके लिए प्रोविजन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके साथ २ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हाई स्कूल और कालेजों की शिक्षा हमारे देश को आग नहीं बढ़ायेगी; जब तक हम ग्राम में रहने वालों के लिये प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर देते । उस समय तक हमारा हिन्दुस्तान और उसके साथ २ हमारा प्रान्त आगे नहीं बढ़ सकता । शिक्षा के मद को देखने से यह ज्ञात होता है कि इस बारे में कुछ भी संकेत नहीं । इसके लिए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्षेत्र जागीरदारों के अधीन थे उनमें इस प्रकार की शिक्षा का बिलकुल अभाव था; वहां पाठशालायें खोलकर उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का विकास बहुत आवश्यक है । इस ओर ध्यान रखेंगे तो इस प्राथमिक शिक्षा के लिये म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को मदद करें । इसके अलावा शिक्षा प्रसार के दूसरे साधन भी मौजूद हैं । राजस्थान में कई संस्थायें मौजूद हैं; वे कितना जन हितकारी कार्य कर रही हैं शिक्षा का प्रसार कर रही हैं; लेकिन खेद है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया । केवल स्टेटस (राज्यों) को मेंटेन किया जा रहा है । मेरे ख्याल से इस ओर सरकार ध्यान दे।

शिक्षा की दृष्टि से मैं अर्ज करना चाहता हूं माइनिंग (खनिज) के कालेज के बारे में । राजप्रमुख के अभिभाषण में भी जिसका जिक्र किया गया था उस बारे में मेरा निवेदन है कि बजट में उसके लिये कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। मैं समझता हूं कि माइनिंग (खनिज) की दृष्टि से उदयपुर ही एक ऐसा स्थान है जो इसके लिये बड़ा उपयुक्त है । मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में अवश्य ध्यान दें ।

अब मैं रोडस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं आज हमारे मेवाड़ रियासत के थानों को लीजिये; जिनके पास पूरे मकानात नहीं । तहसीलों की बिल्डिंग (मकानों) को लीजिये; जिनकी कई अरसे से मरम्मत नहीं हुई। इसी तरह से बिल्डिंग (मकान) और रोडस के लिये अवश्य प्रोविजन (प्रबन्ध) होना चाहिये । मेरे ख्याल से इस प्रकार की कोई पंच वर्षीय योजना को लेकर हमारी सरकार चले ये सब कठिनाइयें आसानी से दूर हो सकती हैं और हमारे प्रान्त का सब तरह से विकास हो सकता है । पंच वर्षीय योजना के रूप में कोई रूपरेखा होने पर ही हमारे प्रान्त का विकास हो सकता है ।

इस बजट (आय-व्ययक के अन्दर जो एक खास मद है वह है फेमिन रिलीफ (दुर्भिक्ष निवारण) के लिये रखी गई रकम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेमिन रिलीफ (दुर्भिक्ष-निवारण) के लिए डेढ़ करोड़ रुपया रखा गया है। इस सदन के सामने मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं होता कि यदि यही कांग्रेस सरकार के बजाय कोई दूसरी सरकार होती; विरोधी दल के नेता के कहने के अनुसार, पहले जो रियासतें थी करोड़ों रुपया इस कार्य के लिए खर्च किया करती थी। वे कह ही सकते हैं; लेकिन कार्य करके नतीजा जब सामने आता है। तब पता चलता है। सही मायने में तभी ज्ञात हो सकता है। फैमीन रिलीफ (दुर्भिक्ष-निवारण) कार्य के लिए हमारे मंत्री महोदय ने व फैमिन कमिश्नर ने जिस संजीदगी और तहेदिल से काम किया है वह इस सदन के सामने प्रशंसनीय है। ऐसी बातों का निवेदन कर मैं कोई सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो कार्य प्रशंसा के योग्य हैं उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इस बजट (आय-व्ययक) को देखने से विदित होगा कि जो घाटे का बजट है, जो हमारे सामने आमदनी के जरिये बताये गये हैं उनमें सिर्फ आमदनी टैक्स (कर) के जरिये ही होना बताई। आमदनी का नया जरिया उत्पादन को बढाने से हो सकता है। इन्डस्ट्रीज (व्यवसायों) का हम केन्द्रीयकरण नहीं कर पा रहे हैं सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम अपने प्रान्त के सिंचाई के साधन बढ़ावें; हमारे यहां जो भूमि खाली पड़ी है उस पर खेती करें। हमारे यहां ऐसी कई हजार बीघा जमीन खाली पड़ी है जिस पर खेती की जा सकती है; तभी हमारा प्रान्त आगे बढ सकता है। मैं मानता हूं कि सिंचाई के लिए जो रकम रखी है वह बहुत अच्छी रकम है। साथ ही मुझे आप माफ करेंगे यदि मैं सिंचाई मंत्री महोदय से यह अर्ज करूं कि वे बड़ी योजनाओं के साथ साथ जैसे गंग नहर, घग्घर नहर आदि के साथ साथ हमारे प्रान्त में जो भारतवर्ष में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह जय समुद्र है उसकी ओर भी ध्यान दें। तो उनको ज्ञात होगा कि इसका उपयोग ठीक तरह से नहीं हुआ। पहले भी रियासतों के समय में भी और राजस्थान बनने के बाद भी उसका उपयोग नहीं किया गया। पिछली राजस्थान सरकार ने उस ओर ध्यान दिया, उस पर कुछ खर्च किया तो उसका प्रत्यक्ष फल हमारे माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने देखा ही है। उस झील के पानी से मेरे ख्याल से १ लाख बीघा भूमि की सिंचाई की जा सकती है, लेकिन दुख होता है यह देखकर कि उस ओर आज हमारे बजट में कुछ भी रकम रखी नहीं गई है। अगर उसमें एक चौथाई भी नहर निकाल दी जाय तो उसके पानी से १ लाख बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सिंचाई मंत्री महोदय इस ओर ध्यान रखेंगे और इस बजट में नहीं तो सप्लिमेन्टरी (अनुपूरक) में इसका प्रोविजन (प्रबन्ध) जरूर रखेंगे।

श्री हरिदत्त: माननीय अध्यक्ष इस बजट के विषय पर जैसा कि मैं दोनों पक्ष के भाषणों को सुन कर अन्दाजा लगा सका हूं, एक ऐसी समस्या पैदा करदी है जिसमें दोनों दलों के व्यक्ति अपने अपने मस्तिष्क के बल को लगा कर, धारा प्रवाह से बोलते हुए भी, अभी तक किसी खास निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। एक पक्ष की तरफ से इसका समर्थन हो रहा है तो दूसरी ओर से यह ध्यान दिलाया जाता है कि इसमें बहुत सी कमियें रह गई हैं। यह तो दोनों पक्ष के सदस्यों ने मान ही लिया है कि इस बजट में कुछ कमियें अवश्य रह गई हैं।

मैंने विपक्ष के माननीय मित्र की तरफ से, अपने लीडर ऑफ ओपोजिशन के बाबत इन शब्दों को सुना कि उन्होंने कहा "इस बजट में ये कमियें रह गई है ये खुद कुछ दिन पहले पिछली सरकार में मिनिस्टर थे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आप मिनिस्टर थे, आप कैसे थे? और आज वहां से कुर्सी बदलते ही आप कुछ से कुछ कैसे हो गये"? मगर मैं यह कहूंगा कि चेन्ज ऑफ साइड का महत्व अवश्य है। यदि आप भी उधर से उठकर इधर आ बैठें तो आप भी यही कहेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं वह यह है कि एक समय एक गडरिया विक्रमादित्य के तख्त पर पहुंच गया था, जो एक टीबे के नीचे दबा हुआ था। उस तख्त पर बैठ कर वह अपनी बुद्धि को लगाकर बड़े बड़े जजमेन्ट्स करने लग गया। इसी तरह इस जमाने में भी हम देखते हैं। हम भी यहां कुछ न कुछ बदल ही जाते हैं जब हम इस हॉल में आते हैं। हम बाहर कुछ और होते हैं। इस बात को वे स्वयं स्वीकार करते हैं। इधर बैठने और उधर बैठने में अन्तर् अवश्य है।

लॉ एन्ड ऑर्डर के लिये पुलिस रखना निहायत जरूरी है। इस सम्बन्ध में यह जो कहा जाता है कि हमारे यहां डकैतियें बहुत हो रही हैं और हमारे प्रोविन्स को प्रोविन्स ऑफ डैकोईट्स कहते हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि इस पर अवश्य विचार करना चाहिये; क्योंकि इस पर दो करोड़ से ज्यादा रुपया हमको खर्च करना है। इस सिलसिले में मैं यह कहूंगा कि यदि हमारे यहां राम राज्य कायम हो जाय अर्थात् पंचायत राज्य बन जावे तो हमारे यहां पुलिस राज्य की हमें कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि हम हमारे यहां धनाढ्यों की तरफ गौर करके देखें तो हमें मालूम होंगे कि हमारे यहां राजस्थान में ५ प्रतिशत भी ऐसे धनाढ्य नहीं होंगे जिन पर डाके पड़ें। तीन करोड़ रुपया खर्च करके सरकार गरीब किसानों को क्या राहत पहुंचा सकती है; हमें अब यह देखना है। वे ग्रामों के साधनों और सुधारों की तरफ देखें कि उन्हें क्या क्या करना है। ऐसे पुलिस राज्य से वह राज्य अच्छा है जिसमें कुछ धनाढ्यों के कुछ रुपये निकल जावें तो गरीबों पर इसका कोई असर पडने वाला नहीं; गरीब जनता को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोई डाका गरीबों पर नहीं पड़ता। यदि दो करोड की जगह चार करोड भी बढ़ते और उससे किसानों को राहत मिलती तो भी ज्यादा अच्छा होता। इसलिए ५ प्रतिशत लोगों के लिए इतना व्यय करना और उसकी तरफ इतना ध्यान देना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि ९५ प्रतिशत लोगों की ओर। यदि इसके पीछे कोई दूसरा आशय हो तो वह बात दूसरी है। मैं इतना कह कर अपनी एक बात पर आ जाऊंगा कि दर असल बजट को क्यों नीरस बनाया जा रहा है। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि बजट नीरस बन गया है। रुपया सब को प्यारा लगता है. दूसरों की जेब में पड़ा रूपया भी प्यारा लगता है तो फिर किस तरह से अपनी जेब में जो रूपया है उसको हमारे पास रखें नहीं। रुपये को हमें अपने पास रखना चाहिये। यदि हम अपने रुपये को अपने पास नहीं रखेंगे तो हमारी वही हालत होगी जैसी की एक किसान की होती है। वह हमेशा अपने बोहरों पर बैठा रहता है। उसको जब जरूरत होती है बोहरे से रूपया ले लेता है और बोहरे का उस पर सदा अंकुश बन रहता है। उसी प्रकार आप रूपया

सेन्टर से लेते रहें तो आपको काफी रूपया मिल जावेगा । मगर उसके यह मायने होंगे कि बोहरे के पास अपनी गर्दन को आपको फंसाना होगा । जब किसान अपने लड़के की शादी करने लगता है तो रूपया बोहरे से ले जाता है और बोहरे को भी बरात में साथ ले जाता है । बेटी वाला कहता है संबन्धी कौन है तो बोहरा खुद कह देता है मैं हूं । इसी तरह में अर्ज करूंगा कि हम अब ऐसे सीधे सादे किसान नहीं रहे । हमारी पूंजी ऐसी नहीं है जिसके संबन्ध में हम अन्धेरे में रहें । इसलिए सब से पहले मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमें सब से पहले अपनी आमदनी की तरफ देखना चाहिये । आमदनी आसानी से बढ़ाई नहीं जा सकती । हमें अपने पिछले साल के आंकडों को देख कर चलना चाहिये । हो सकता है कि ये आंकडे इस साल बढ जावें या पहले से कुछ कम भी हो जावें । मगर खर्च एक ऐसी चीज है जिससे हम जितना ज्यादा बढ़ाना चाहें, बढा सकते हैं । हम कई लाख तक खर्च कर सकते हैं । इस लिहाज से मुझे यह कहना है कि खर्च की तरफ से हमें बाहर से ऋण लेकर अपनी गर्दन को नहीं फंसानी है । हमको अपनी आमदनी को देखना है । हमारी आमदनी तीन बातों पर निर्भर है ।

१. लेन्ड रेवेन्यू: २. एक्साइज ड्यूटी और ३. अदर टैक्सेज । लैंड रेवेन्यू में रिवाइज्ड एस्टिमेट १९५१–१९५२ से कुछ ज्यादा रुपया दिखाया है । हमारी लैंड रेवेन्यू जो दिखाई गई है वह दर असल कमी के साथ है जो एकाउन्ट १९५०-५१ का था उसके मुकाबले में करीब ५० लाख का घाटा पड़ता है और जो हमारे ऐस्टिमेट १९५१ के हैं उसके मुकाबले में कई लाख का घाटा दिखाई देता है । इससे यह साफ जाहिर होता है कि हम घाटे की तरफ जा रहे हैं । हमारा सब से बड़ा इनकम का सोर्स यही है । यदि इस तरफ हम तवज्जुह नहीं देंगे और सोचेंगे की जो कमी है वह ठीक है और उसको दढोतरी के साथ दिखा दें; यह ठीक नहीं । हमको अपनी आमदनी को बारीकी के साथ देखना है । हमको सच्चाई के साथ अपनी आमदनी दिखानी होगी और जो भी घाटा है उस पर हमें मिल जुल कर विचार करना चाहिये; उसे छुपाना नहीं चाहिये । आखिर हमको देखना है कि यह कमी क्यों हो रही है? मैं कहूंगा कि यह कमी जो रेवेन्यू विभाग में हो रही है वह अफसरों की पूर्णतया निगरानी की कमी के कारण हो रही है । और इसकी कमी के कारण जो आज हैं वे कल भी रहेंगे; यदि हमने अपने रेवेन्यू विभाग की तरफ तवज्जुह नहीं दी । मेरा तो यह तजुर्बा है कि रेवन्यू डिपार्टमेंट ३–४ साल के बाद जो एक रेवेन्यू का खास जरिया है यदि इसी तरह से उस पर तवज्जुह दी जाती रही तो एक तुच्छ विभाग को तरह रह जायगा । अभी जो ओफिसर हैं उनकी दूसरी ड्यूटी उनके साथ साथ लगादी जाती हैं । जिससे कि वे अपने प्रान्त का दौरा नहीं कर सकते । माल गुजारी एक ऐसी चीज है जिसके लिए अफसरों को दौरा करते रहना चाहिये । मैं दूसरी जगहों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता मगर भरतपुर रियासत में माल गुजारी का काम कलेक्टर के सुपुर्द है । इसके साथ साथ दूसरे भी बहुत से काम उसके जिम्मे रहते हैं । माल गुजारी के अफसर के पास फौजदारी काम बिल्कुल नहीं होना चाहिये । पहले वहां पर ८ अफसर, दो कलेक्टर, ३ सब जज और ३ मुनसिफ थे; आज कल वहां पर ८ के बजाय

९ अफसर हैं मगर उसके साथ फौजदारी काम लगा हुआ है और इस वजह से उनको दौड़ा करने के लिये फुरसत नहीं मिलती है। राज का खर्चा तो यों का यों होता है मगर अफसर जाकर वहां की हालत को नहीं देख सकता। पटवारी जैसी रिपोर्ट पेश कर देता है उसी पर वह मुकामी अफसर हुक्म लिख देता है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जुडिशियरी और एग्जिक्युटिव दोनों अलग अलग होने चाहिये. यदि हमें अपनी माल गुजारी बढ़ानी है तो रेवन्यु डिपार्टमेंन्ट को बिल्कुल ही सेपरेट कर देना चाहिये ताकि वह अपना सारा समय इसकी वसूली में लगा दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अर्ज करूंगा कि हम कमी की तरफ चलते जावेंगे।

अब मैं अपने वक्तव्य को थोड़े समय के अन्दर ही समाप्त करने के लिए जल्दी रफ्तार से चलकर संक्षेप में कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपका ध्यान एक्साइज ड्युटी पर दिलाना चाहता हूं इसके साथ ही मैं शराब पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ हमको खास तवज्जुह देनी चाहिए। यों तो यह एक तरह का पानी ही है। मगर जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वे इसके सम्बन्ध में ज्यादा जानते हैं कि यह दरिया किस तरह से बहाया जाता है। लेकिन जो बात जाहिद है उनका यह साफ कहना है कि इस दरिया को इस तरह से न बहने दिया जावे। इसको खत्म करने के लिए और इसकी तलहटी में रूकावट पैदा करें। बजट के लिहाज से हम देखते हैं तो १९५० से यह बढ़ती हुई आमदनी चली आती है। इसका नतीजा यह होता है कि इस आमदनी के बढ़ने के बाद हम इस सम्बन्ध में अपने आपको बदनाम करते हैं और दूसरे नेशन्स की नजरों में हम शराब की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमको चाहिए कि इस दरिया की जो तलहटी है उसको बिलकुल खुश्क कर दें, तो यह बहुत अच्छा हो। अगर उसको खुश्क नहीं करना है तो हमें चाहिए कि दरिया को जैसे वह बह रही है, बहने दें। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर उसके शौक करने वालों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है।

तीसरी बात दूसरे करों के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि कस्टम्स सब से बड़ी चीज है। यह किस तरह जारी रहेगी जब कि कमेटी ने यह प्रोपोजल किया है कि इसको खत्म कर दिया जावे। लेकिन देखते हैं कि यह तो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। इन्टर्नल वेलफेयर (Internal welfare) कम होता जा रहा हैं। ड्युटी को बढ़ाने से तमाम टैक्स काश्तकारों पर पड़ते हैं और किसान दिन ब दिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। अभी २ सदन के सामने एक माननीय महोदय ने कहा कि किसानों पर टैक्स, जमीन पर टैक्स, कोई चीज बेचते हैं तो टैक्स, कोई चीज खरीदते हैं तो टैक्स लगते है। जब बाजार में जाकर वह कुछ खरीदता है तो उस पर सेल टैक्स लगता है। इस प्रकार सब टैक्स किसानों पर पडते हैं। इन सब को नजर अन्दाज करके थोड़े से धनाढ्यों के लिये करोड़ों रुपया पुलिस पर, उनके प्रोटेक्शन के लिए लगाना चाहती है। करोड़ों रूपये खर्च करके किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती है, कस्टम्स उन पर कम किया जाना बहुत जरूरी है, उसको नहीं किया जा रहा है। हाल ही में

कस्टम्स का नतीजा यह निकला कि जो बोर्डर का एरिया है वहां से सरसों बाहर जाकर बाहर के माल से कोम्पीटीशन नहीं कर सकी; इससे लाखों रुपया का नुकसान उठाना पड़ा और इन्कमटेक्स भी बहुत कम हो गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि अर्थ शास्त्र के विशेषज्ञ इस पर अवश्य ध्यान दें। इसके अलावा इन्कम ओफ फूड में एक करोड़ सत्तर लाख की आमदनी दिखाई गई है। यह एक ऐसा रुपया है जिसका नाज हमारे यहां जमा है मैं पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या करती है? बहुत सा नाज पड़ा २ सड़ जाता और फिर उसे बाहर फेंकना पड़ता है। दूसरी जगहों का क्या हाल है; मैं नहीं जानता। भरतपुर के बारे में तो मैं कह सकता हूं। स्टोकों की यह हालत है कि अनाज पड़ा २ सड़ रहा है, बोरियों की बोरियों सड़ जाती है और उन्हें फेंकना पड़ता है। हम इस कीमत को नहीं दिखा सकते। जो दिखाई गई है यह भी एक भूल है। दूसरी जगह भी ग्रेन रखा खराब हो रहा है

कुछ शेयर्स रेल्वेज में थे वे दो करोड़ ६१ लाख के बताये गये हैं और उसमें से ७५ लाख के शेयर्स सेन्टर ने खरीद लिए और १८६ लाख के स्टोक में है। अभी बताया गया है कि इनसे डिवीडेंड नहीं आ रहा है और इनको स्टोक आफ एक्सचेंज में भी नहीं दिखाया जा रहा है। हमारी पूंजी जो इस तरह से Blocked है वह भी हमें नुक्सान पहुंचाती है। इस प्रकार की सभी बातों पर ध्यान देना है यदि हमें अपना बजट ठीक करना है।

एक आइटम ओवर ड्राफ्ट का है। ९३२११ लाख केपिटल एक्सपेन्डिचर पर लिया है। इसमें से ३६१ लाख केपिटल एक्सपेन्डिचर हैं और १७३ लाख Food Procurement पर है। इस तरह ५,३४ लाख का हो जाता है जिससे हम यह ख्याल करें कि ९३२ में से ५३४ लाख हमारे पास मौजूद हैं। बाकी करीब चार करोड़ के और ३॥ करोड़ हमने इन्वेस्टमेन्ट में से खर्च किया। इस प्रकार ७॥ करोड़ के करीब हमने ज्यादा खर्च किया है और इसी प्रकार यदि ज्यादा खर्चा होता रहा तो क्या गवर्नमेन्ट इस मशीनरी को चला सकेगी इसके अलावा एक एमाउन्ट रिहेबिलिटेशन के कर्जे में दिया गया है। यह रुपया सेन्टर से दिया गया है। मगर सेंटर ने इसकी वसूली की सब जिम्मेदारी हमारे पर लाद दी है, तो यह रुपया कैसे वसूल होगा? यह मैंने एक साइड सदन के सामने रखी है।

(माननीय अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

अब चूंकि मुझे समय नहीं है इसलिए मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

विधान कार्य

राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक (संशोधन) अधिनियम, १९५२

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक अधिनियम, १९५१ को संशोधित करने के विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक अधिनियम १९५१ को संशोधित करने के विधेयक को पुर: स्थापित (प्रस्तुत) करने की आज्ञा दी जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक अधिनियम, १९५१ को संशोधित करने का विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अब सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९५२ ई०, प्रात:काल ८–३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(इसके पश्चात् सदन १२–४५ बजे, शुक्रवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९५२ ई० के प्रात: काल ८–३० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

टाउन हॉल,
जयपुर,
४ अप्रेल, सन् १९५२.

मन्साराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर.